

## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

नये साल की शुरुआत के साथ ही, दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत को भी ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण आर्थिक सुधार में बाधा का सामना करना पड़ा। फिर भी, उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास एवं बैंक ऋण में वृद्धि के कारण समग्र मांग की स्थिति सुदृढ़ है, जबकि आपूर्ति के मोर्चे पर, रबी की बुवाई पिछले साल के स्तर और सामान्य रकबे को पार कर गई है। विनिर्माण और विभिन्न सेवाओं में अभी विस्तार जारी है। ओमीक्रॉन की लहर चंद दिनों तक ही ठहरने की उम्मीद में निकट भविष्य के अनुमान सकारात्मक हैं।

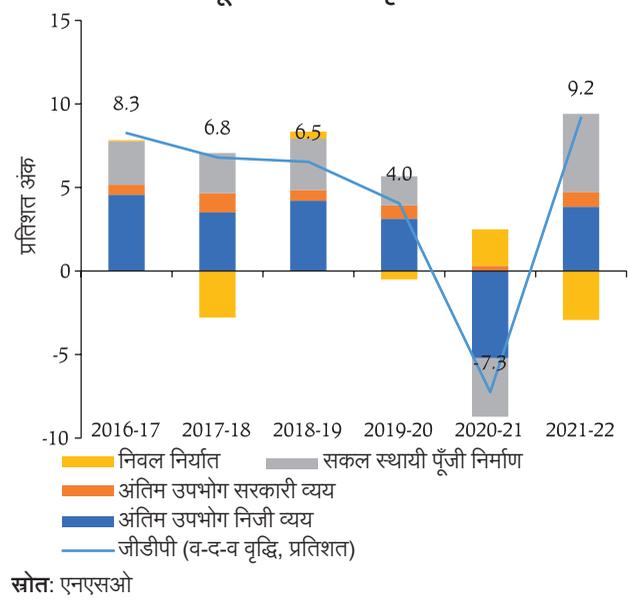
### भूमिका

नये साल में भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में महामारी से पहले के अपने स्तर को पार कर लिया। जैसे-जैसे आर्थिक सुधार मजबूत हुआ निवेश, निर्यात और आयात अपने पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक हो गए (चार्ट 1) और कुल मांग के सभी घटकों में विस्तार हुआ। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 2021-22 में तेजी आई, जिससे समग्र मांग को बल मिला। आपूर्ति में, कृषि क्षेत्र रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के कारण सकारात्मक रहा। औद्योगिक और सेवा गतिविधि में अड़चन के बावजूद सुधार देखा गया, जबकि सेवाओं को अभी तक अपने 2019-20 के स्तर को प्राप्त करना बाकी है।

‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ आलेख के दिसंबर 2021 अंक के बाद से कुछ क्षेत्रों में धीमापन आया है। बाहरी मोर्चे पर, दिसंबर में भारत का मजबूत निर्यात प्रदर्शन भारतीय माल की लगातार मांग

\* यह आलेख कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम. लोकरे, राजीव जैन, शाहबाज खान, विनीत कुमार श्रीवास्तव, अभिलाषा, प्रियंका सचदेवा, अभिनंदन बोराड, प्रशांत कुमार, दीपिका रावत, अक्षरा अवस्थी, ऋषभ कुमार, सत्यार्थ सिंह, रचित सोलंकी, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, साक्षी अवस्थी, राधेश्याम वर्मा, आशीष थॉमस जॉर्ज, श्री देब प्रसाद रथ और श्री समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

चार्ट 1: सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में भारत योगदान



को दर्शाता है, जबकि घरेलू मांग में सुधार के कारण आयात में भी वृद्धि हुई है। आने वाले दशकों में निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, ऑप्टिकल और सर्जिकल उपकरण जैसे उच्च तकनीकी उत्पादों की निर्माण-क्षमता महत्वपूर्ण साबित होगी।

महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए नीतिगत उपाय 2021-22 में अपनी पूर्व-घोषित समाप्ति तिथियों तक पहुंच गए। परिणामस्वरूप, जहाँ कुछ चलनिधि उपाय समाप्त हो गए हैं, ज़रूरतमंद क्षेत्रों को तय सहायता प्रदान करते हुए, अन्य विनियामक उपाय, जैसे - निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन का स्थगन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा लाभांश के भुगतान पर रोक, और पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन का स्थगन - को, विस्तारित चुकौती-अवधि और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से बचने के लिए, फिर से संरेखित किया गया है।

बैंक ऋण वृद्धि खुदरा क्षेत्र में बढ़त के साथ एक क्रमिक सुधार का संकेत दे रही है, हालांकि कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स में ऋण प्रवाह-संकुचन बना हुआ है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने हाल ही

में, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर अपनी रिपोर्ट, 2020-21 जारी की। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 अंत के 8.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 अंत में 7.3 प्रतिशत और आगे सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) सितंबर 2021 तक बढ़कर 68.1 फीसदी हो गया, जो मार्च 2020 में 66.2 था।
- जैसा कि आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा दर्शाया गया है, स्थिर आय और व्यय में गिरावट की बदौलत, एससीबी की लाभप्रदता में मार्च 2020 के अंत में 0.2 प्रतिशत से मार्च 2021 के अंत में 0.7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई जो सितंबर-2021 में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गई।
- उच्च प्रतिधारित आय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूँजीकरण और पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा बाजार से पूँजी जुटाने के सहयोग से, एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 के अंत में 14.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 16.3 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत में 16.6 प्रतिशत हो गया।
- कुल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2020 के अंत में 0.4 प्रतिशत थी। यह अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मानक अग्रिमों के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना को दर्शाती है। साथ ही यह, खुदरा ऋण और एमएसएमई के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0 के कारण सितंबर 2021 तक 1.8 प्रतिशत हो गई।

इस आलेख के बाकी हिस्सों को चार खंडों में बाँटा गया है। खंड II में हाल के वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन, खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा की गई है और अंतिम खंड में आलेख का समापन किया गया है।

## II. वैश्विक परिदृश्य

कोविड-19 के फिर से आने और नए वेरियंट के कारण लंबी अवधि की आर्थिक संभवनाओं को गंभीर जोखिम है। 10 जनवरी 2022 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 306 मिलियन मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमीक्रॉन वेरियंट के उच्च प्रसार क्षमता के कारण, कई देशों ने फिर से लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और अन्य रोकथाम उपाय लागू कर दिए हैं। अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है क्योंकि प्रोत्साहन-प्रेरित कदम से उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जारी है। इसके कारण मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण में तेजी आ रही है। आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और पोत-परिवहन शुल्क में कुछ ढील दी जा रही है, हालांकि, महामारीजन्य मुद्रास्फीति में 2022 के उत्तरार्ध तक कमी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, वैश्विक संवृद्धि की गति मंद हुई है।

विश्व बैंक ने 11 जनवरी 2022 को जारी अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिकी पूर्वक्षण (जीडपी) रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया है कि कोविड-19 का लगातार उभार, नीतिगत मदद में न्यूनता और लगातार आपूर्ति बाधाओं के मद्देनजर वैश्विक सुधार में तेज गिरावट आएगी। अमेरिका और चीन के संवृद्धि पूर्वानुमानों को 2021 और 2022 (सारणी 1) दोनों के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र मंदी उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए बाहरी मांग को नीचे ला देगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई) 2023 तक उत्पादन में पूरी तरह से सुधार हासिल कर लेंगी, जबकि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) अभी भी अपनी पूर्व-महामारी स्थिति से 4 प्रतिशत कम रहेगी।

ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) दिसंबर 2021 में तीन महीने के निचले स्तर 54.3 पर समाप्त हुआ, हालांकि उसमें लगातार 18 महीनों तक विस्तार देखा गया। साथ ही, वैश्विक सेवाओं का पीएमआई भी दिसंबर में तीन महीने के निचले स्तर 54.6 पर आ गया, हालांकि इसने विनिर्माण - जो पिछले महीने के 54.2 (चार्ट 2) के स्तर पर स्थिर था - से

**सारणी 1: चुनिंदा उन्नत और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि अनुमान**

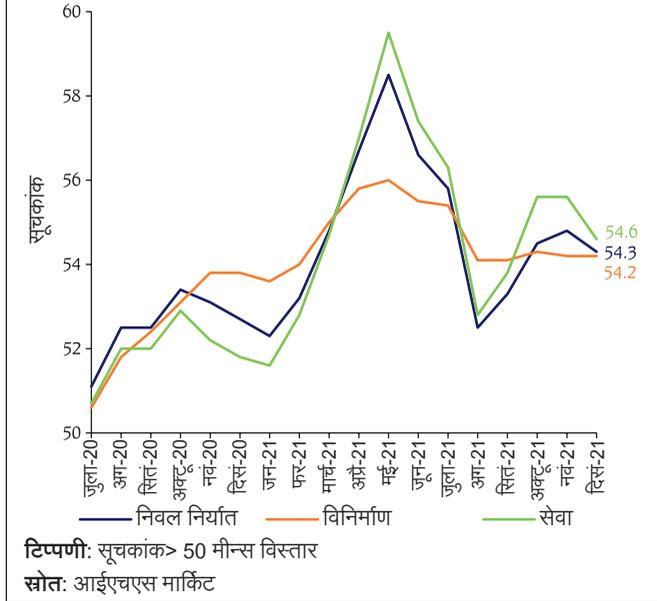
(प्रतिशत)

देश	2021		2022	
	जून 2021	जन 2022	जून 2021	जन 2022
 विश्व*	5.7	5.7	4.5	4.4
<b>उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ</b>				
 यूएस	6.8	5.6	4.2	3.7
 यूरो क्षेत्र	4.2	5.2	4.4	4.2
 जापान	2.9	1.7	2.6	2.9
<b>उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ</b>				
 ब्राजील	4.5	4.9	2.5	1.4
 रूस	3.2	4.3	3.2	2.4
 भारत#	<b>8.3</b>	<b>8.3</b>	<b>7.5</b>	<b>8.7</b>
 चीन	8.5	8.0	5.4	5.1
 दक्षिण अफ्रीका	3.5	4.6	2.1	2.1

\* : पीपीपी भारत # : राजकोषीय वर्ष पर आधारित भारत के आँकड़े

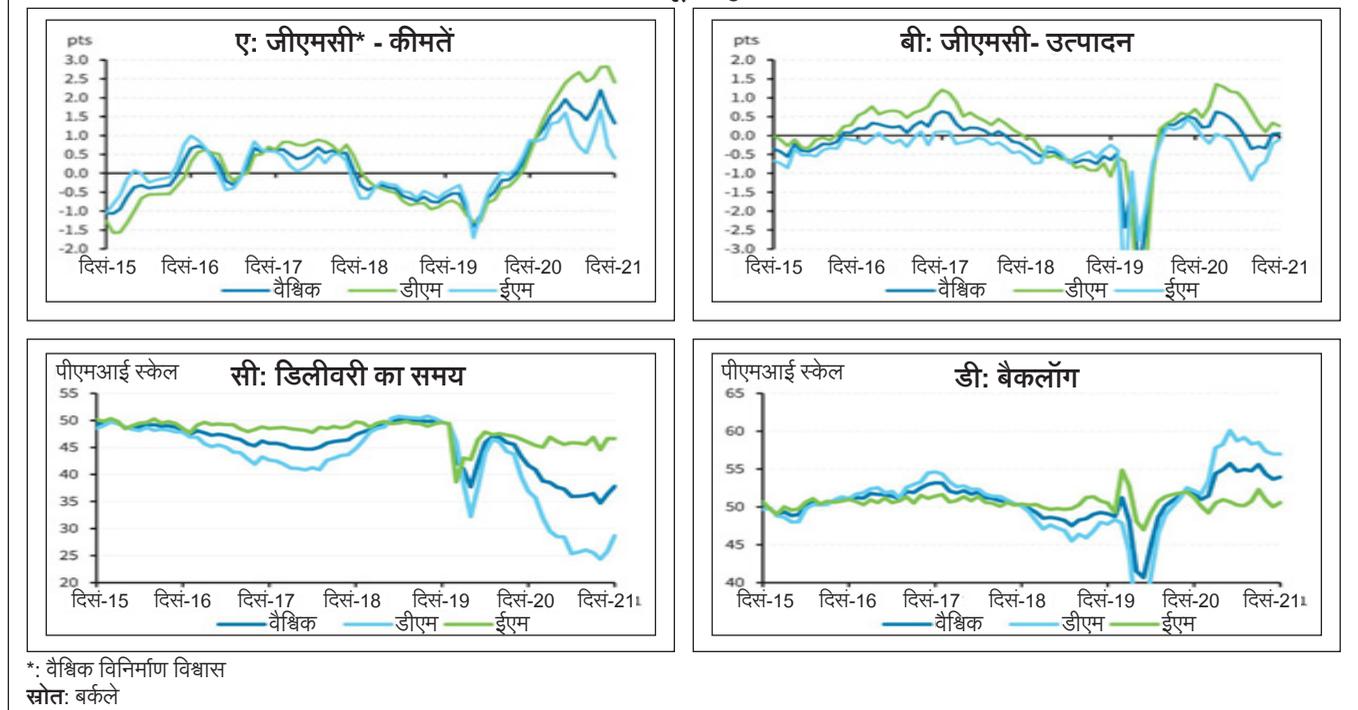
स्रोत: विश्व बैंक

**चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई**

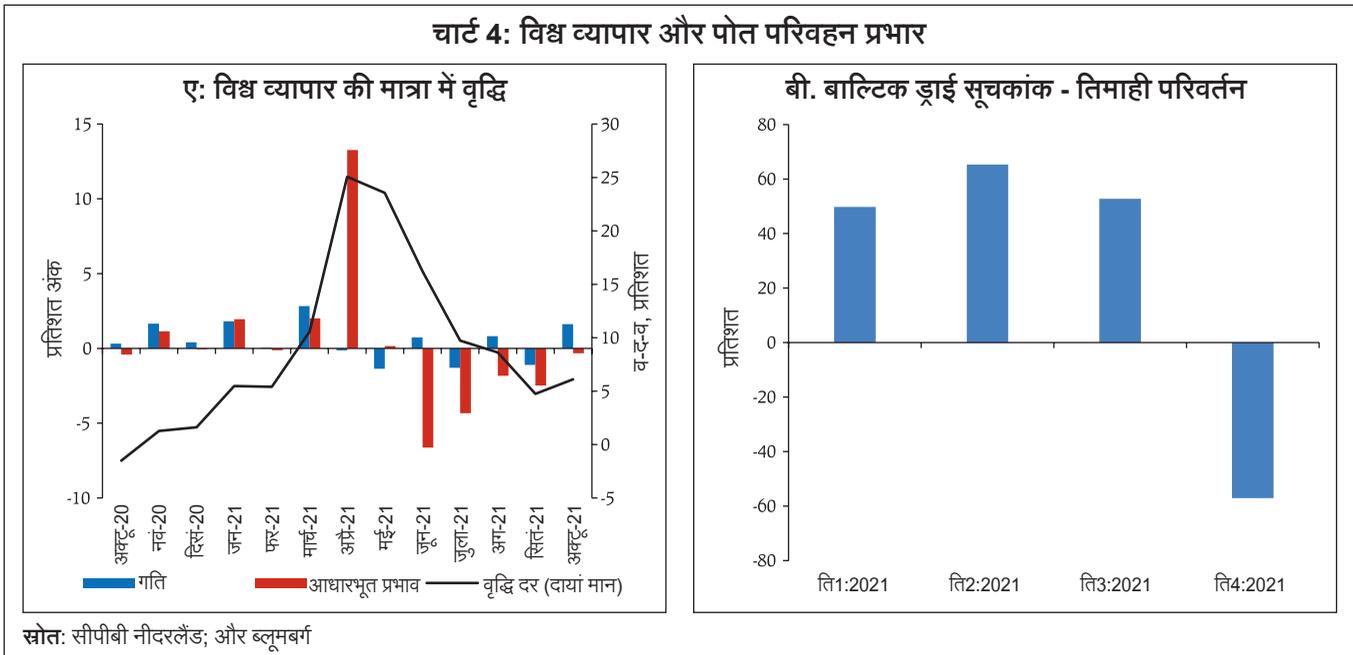


बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि मुद्रास्फीति और आपूर्ति शृंखला में दबाव बने रहे लेकिन इनमें कमी के संकेत हैं। निविष्टि लागत और उत्पादन कीमतों में आठ महीनों में सबसे कमजोर वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विक्रेता का आपूर्ति-समय नौ महीनों में न्यूनतम था (चार्ट 3)। न्यूयॉर्क फेड का वैश्विक आपूर्ति शृंखला

**चार्ट 3: वैश्विक आपूर्ति शृंखला के कारक**



**चार्ट 4: विश्व व्यापार और पोत परिवहन प्रभार**



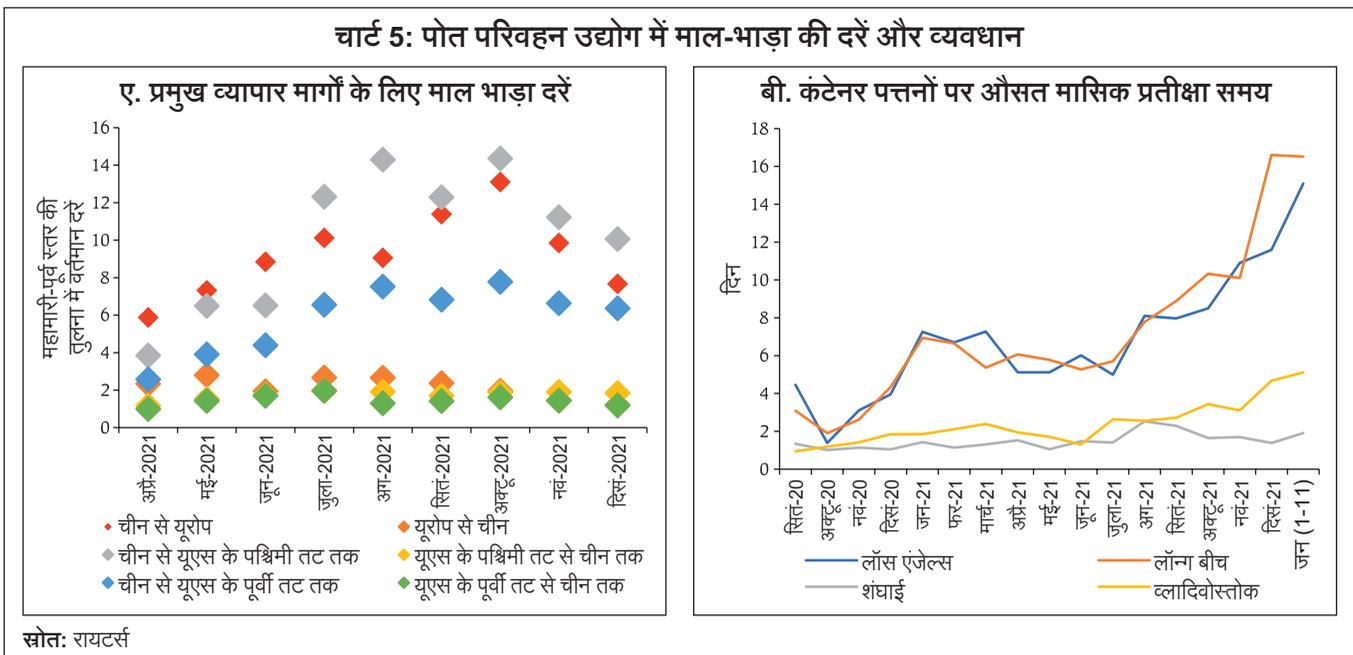
दबाव सूचकांक<sup>1</sup> चरम पर है और आगे चलकर मध्यम होना शुरू हो सकता है।

बाहरी मांग के मोर्चे पर, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), लगातार पांच महीनों (चार्ट 4ए) की गिरावट के बाद अक्तूबर 2021 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई। अक्तूबर की शुरुआत

में 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी 2021 की चौथी तिमाही में नरम हुआ (चार्ट 4बी)।

दिसंबर 2021 में सभी मार्गों की माल-भाड़ा दरों में भी कमी आई, लेकिन वे अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर (चार्ट 5ए) से ऊपर हैं। हालांकि, ओमीक्रॉन के कारण आपूर्ति शृंखला व्यवधान

**चार्ट 5: पोत परिवहन उद्योग में माल-भाड़ा की दरें और व्यवधान**



<sup>1</sup> <https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/01/a-new-barometer-of-global-supply-chain-pressures/>

बढ़ गए हैं, जिससे टर्न-अराउंड समय और यूएस जाने वाले जहाजों का प्रतीक्षा समय बढ़ गया है (चार्ट 5बी)।

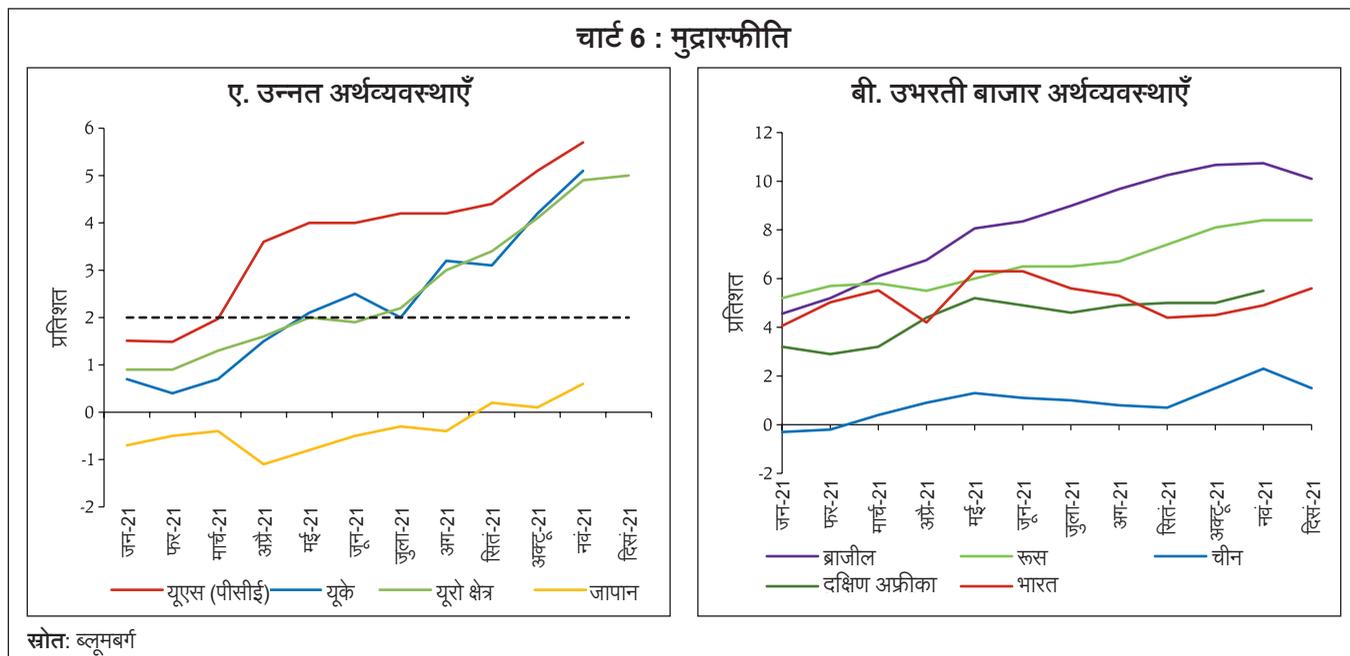
कई क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई (चार्ट 6)। अमेरिका में, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति नवंबर में 5.7 प्रतिशत - करीब 40 साल के उच्च स्तर - पर पहुंच गई, साथ ही मूल पीसीई मुद्रास्फीति भी 32 साल के उच्च स्तर - 4.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 5.0 प्रतिशत की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील में दिसंबर 2021 में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीने के 18 साल के उच्च स्तर 10.7 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गई। रूस में मुद्रास्फीति दिसंबर में 8.4 प्रतिशत पर स्थिर थी।

2021 में दुनिया भर में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारक ऊर्जा, खाद्य और जिंस की कीमतों में तेज उछाल रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 2020 में 32.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021 में 67.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 7ए)। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 2021 में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई - यूरोप में इसकी कीमतें दिसंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं (चार्ट 7बी)। ब्लूमबर्ग क्मोडिटी प्राइस इंडेक्स में 2021 में

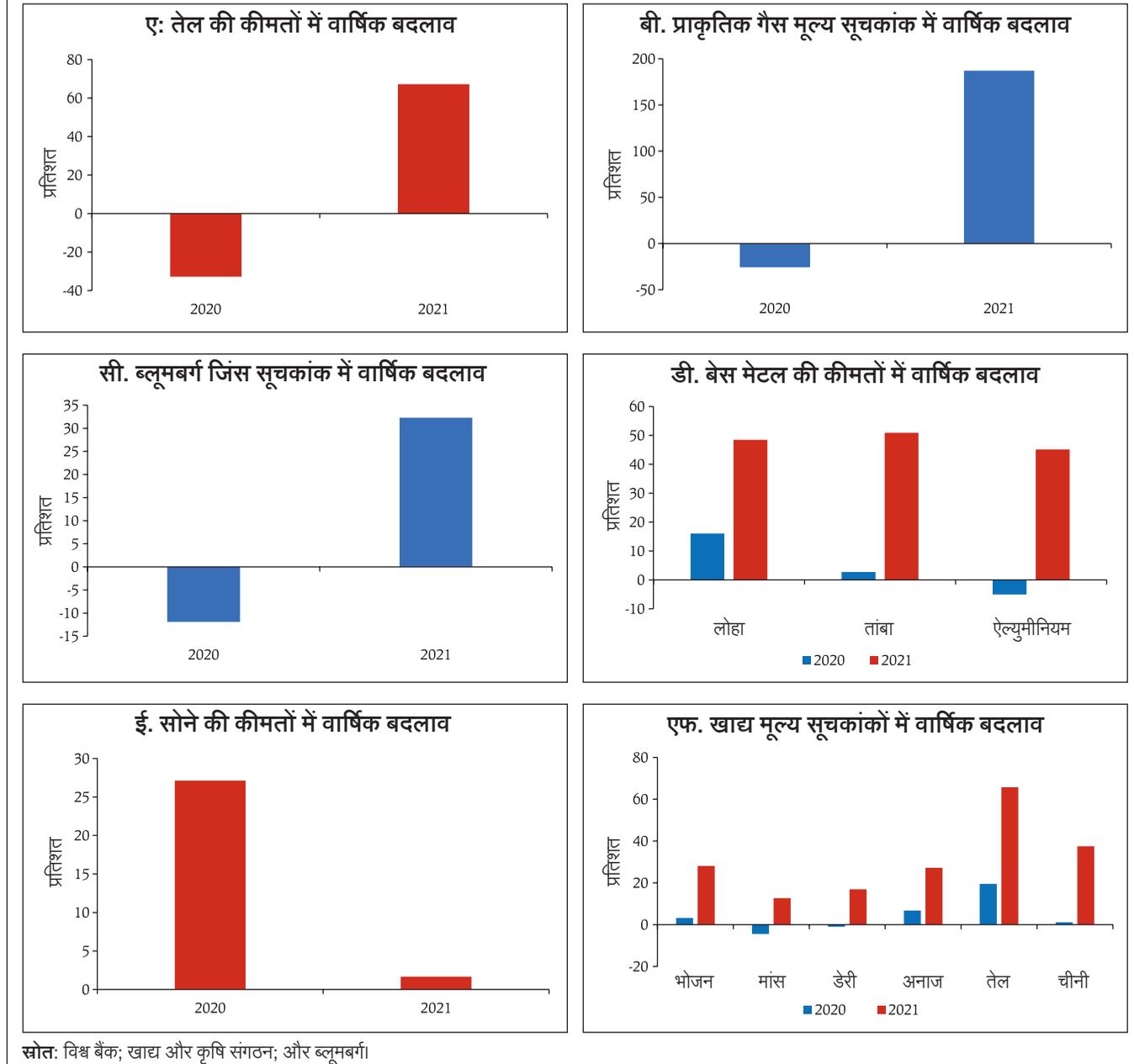
32.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके साथ - विनिर्माण में सुधार के कारण धातु की कीमतें बढ़ीं, 'हरी' धातुओं की अधिक मांग पैदा हुई और महामारी से संबंधित आपूर्ति व्यवधान भी बढ़े (चार्ट 7सी और 7डी)। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में 2021 में केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि पीली धातु की मांग कम हुई और डॉलर में मजबूती आई (चार्ट 7ई)। दिसंबर में मामूली कमी के बावजूद - मौसम संबंधी आपूर्ति में व्यवधान और चुनिंदा खाद्य पदार्थों के लिए चीन से उच्च आयात-मांग के कारण - खाद्य कीमतें 2021 में एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गईं (चार्ट 7एफ)।

वित्तीय बाजार वायरस के फैलाव और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के कारण अस्थिर थे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों में तेजी बनी रही, जबकि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में कम संवृद्धि की संभावनाओं और संबंधित देश के अपने कारकों (चार्ट 8ए) के कारण शेयर बाजार कमजोर रहा। अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में, उच्च मुद्रास्फीति और संवृद्धि परिणामों की प्रतिक्रिया में 10-वर्षीय प्रतिफल बेंचमार्क आम तौर पर 2021 के उत्तरार्ध में बढ़ा, लेकिन मौद्रिक नीति रुख में बदलाव के कारण 2 साल का प्रतिफल 2021 की चौथी तिमाही में ही कम होने लगा। परिणामतः प्रतिफल का फैलाव धीरे-धीरे कम होता गया (चार्ट 8बी)। सुरक्षित आश्रय मांग और फेडरल

चार्ट 6 : मुद्रास्फीति



चार्ट 7: जिंस और खाद्य वस्तुओं की कीमतें

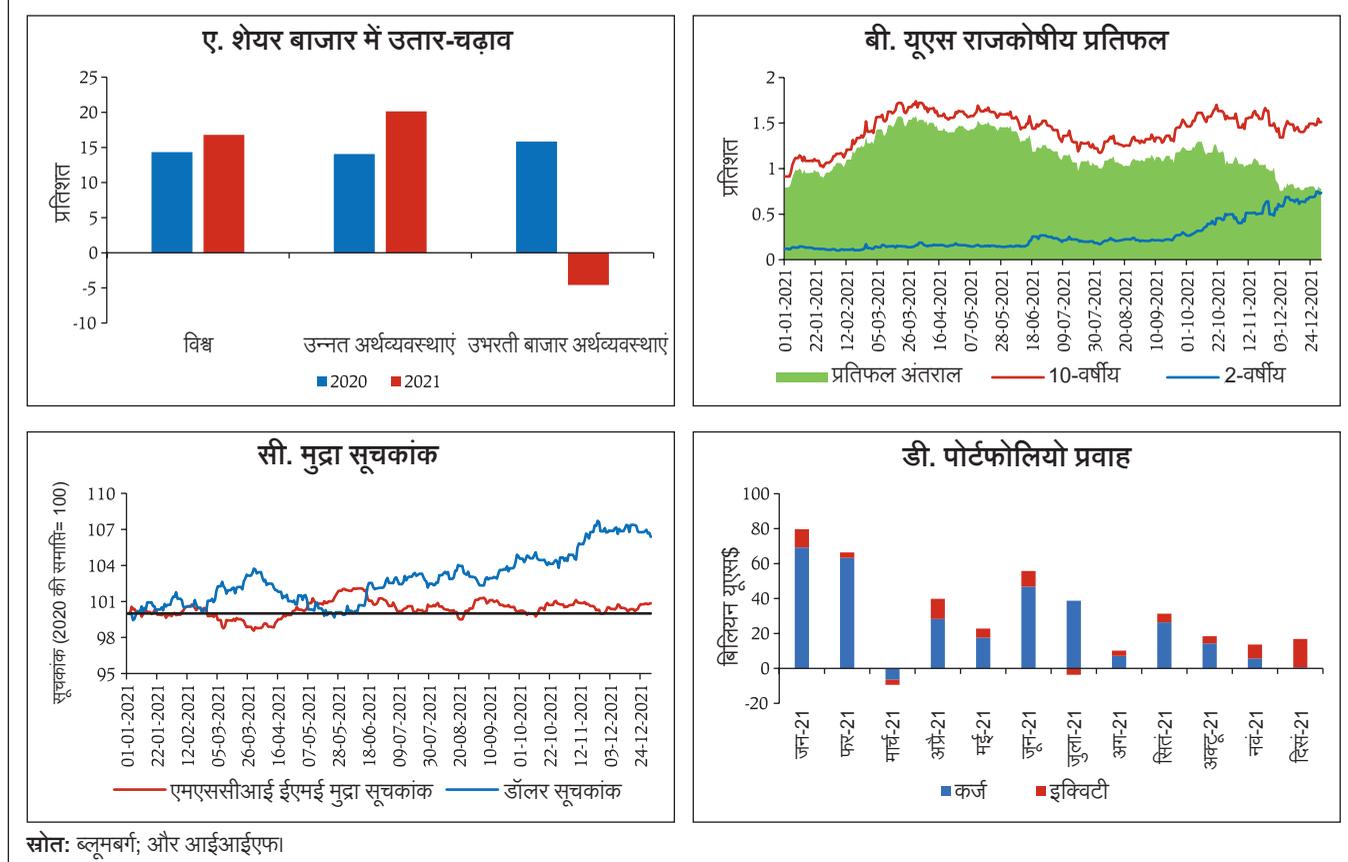


रिज़र्व की तीव्र सामान्यीकरण नीति (चार्ट 8सी) को देखते हुए अमेरिकी डॉलर 2021 के उत्तरार्द्ध में मजबूत हुआ। जैसे-जैसे जोखिम वहन क्षमता में कमी आई, 2021 के अंतिम महीनों में उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी प्रवाह में भी कमी देखी गई, जिसमें ऋण प्रवाह में तेज गिरावट आई (चार्ट 8डी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गौर किया है कि

वैश्विक संवृद्धि के प्रति उच्च जोखिम के माहौल में, फेड द्वारा दरों की तेज बढ़ोतरी से दुनिया भर की वित्तीय परिस्थितियाँ दबाव में आ सकती हैं। अमेरिकी मांग और व्यापार में संभावित मंदी से उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी-बहिर्गमन और मुद्रा-मूल्यहास हो सकते हैं।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, यूएस फेड ने अपनी दिसंबर की बैठक में मासिक टेपर की मात्रा को दोगुना करके अपने आस्ति

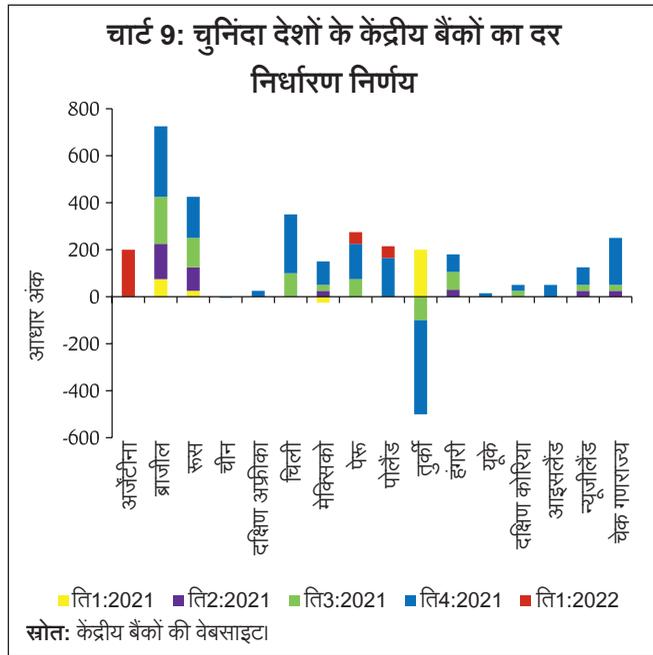
चार्ट 8: वित्तीय बाजार



खरीद कार्यक्रम में तीव्र मंदन का संकेत दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2022 की पहली तिमाही में महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) के तहत आस्तित्व खरीद की धीमी गति और मार्च 2022 के अंत तक पीईपीपी को बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, इसीबी 2022 की दूसरी तिमाही में संपत्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) के तहत खरीद को दोगुना करेगा और धीरे-धीरे 2022 की चौथी तिमाही तक वास्तविक गति पर वापस आएगा। बैंक ऑफ जापान ने मार्च 2022 के अंत तक वाणिज्यिक पेपर और कॉरपोरेट बॉन्ड की अतिरिक्त खरीद को पूरा करने का भी संकेत दिया है और अप्रैल 2022 से, यह महामारी से पहले की खरीद की मात्रा में वापस आ जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी नीतिगत दर में 15 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ दर-बढ़ोतरी समूह में शामिल हो गया। रूस ने दिसंबर में दरों में सातवीं बार बढ़ोतरी की थी। पोलैंड 2022 में 4 जनवरी को 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ दरें बढ़ाने वाला पहला देश बन गया,

जो अक्टूबर 2021 में दरों में बढ़ोतरी के बाद से लगातार चौथी वृद्धि थी। पेरू, अर्जेंटीना और उरुग्वे अन्य केंद्रीय बैंक हैं जिन्होंने 2022 में अब तक (11 जनवरी तक) दरें बढ़ाई हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अपने 1 साल के लोन प्राइम रेट में 5 बीपीएस की कटौती की। अप्रैल 2020 के बाद से प्रमुख नीतिगत दर में यह पहली कटौती थी और इसके बाद दिसंबर में आवश्यक आरक्षित-निधि अनुपात में कमी की गई। तुर्की ने दिसंबर में लगातार चौथी बार कटौती की, जिससे सितंबर 2021 (चार्ट 9) के बाद से 500 बीपीएस की एकमुश्त कटौती हुई।

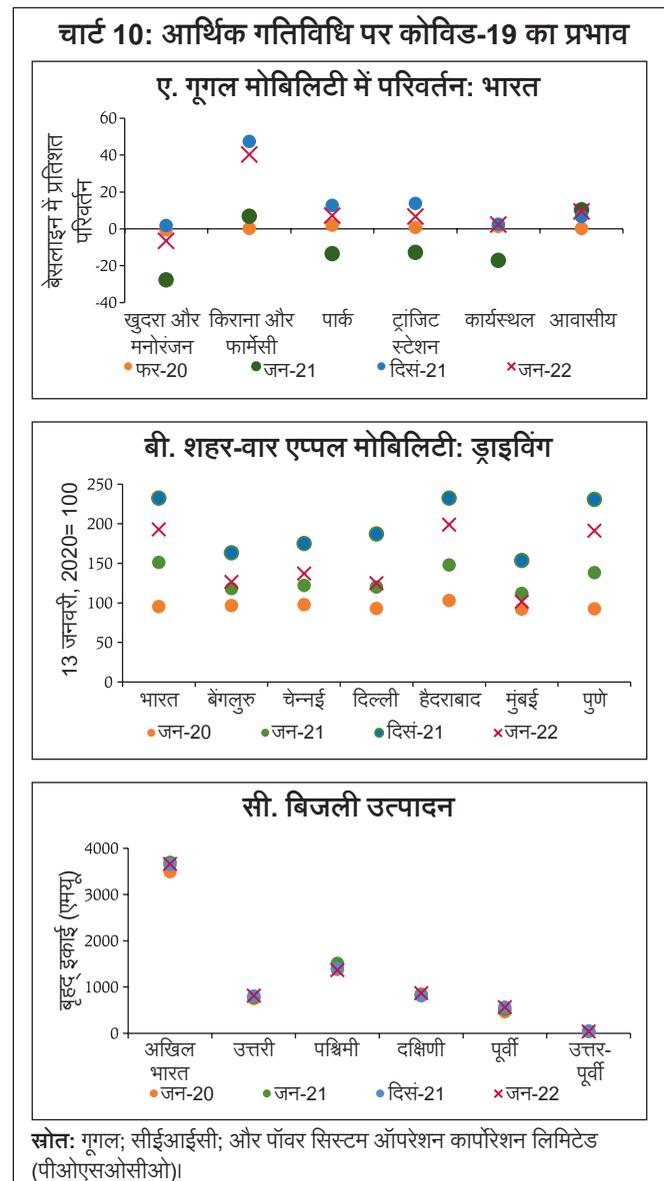
नये साल की शुरुआत में निकट भविष्य का वैश्विक दृष्टिकोण अस्पष्ट बना हुआ है। हालांकि, डेल्टा की तुलना में ओमीक्रॉन तेजी से बढ़ा लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में तेजी से घटा है। इससे यह उम्मीद बँधी है कि ओमीक्रॉन पहली लहर की तुलना में अल्पकालिक सबित होगा।



बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकना पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि, ऐसा दृष्टिकोण भी व्यक्त किया जा रहा है कि विश्व-अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सबसे खराब दौर अभी आने वाला है। इसके कुछ कारक इस प्रकार हैं- पहला, वैश्विक खाद्य कीमतों का संयुक्त राष्ट्र सूचकांक एक दशक के उच्चतम स्तर के बाद, दिसंबर 2021 में 0.9 प्रतिशत फिसला। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में गतिरोध कम हो रहा है और आगे जाकर और कम होने की उम्मीद है। तीसरा, धातु की कीमतें 2021 की दूसरी छमाही में स्थिर हो गई हैं और 2022 में घटने की संभावना है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति, 2021 में बढ़ने के बाद, 2022 में भी पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहेगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने 2021 के अंत तक मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने और फिर उन स्तरों तक घटने - जो धीरे-धीरे बढ़ती श्रम लागत और दुनिया भर में घटती अतिरिक्त-उत्पादन क्षमता के अनुरूप हैं - का अनुमान लगाया था। ओईसीडी-अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2021 की चौथी में 4.9 प्रतिशत से घटकर 2022 की चौथी तिमाही तक 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। चूंकि मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद केवल 2022 के उत्तरार्ध में ही है, इसलिए नीतिगत संतुलन जटिल होते जा रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच रही है जबकि उत्पादन-अंतराल ऋणात्मक बना हुआ है।

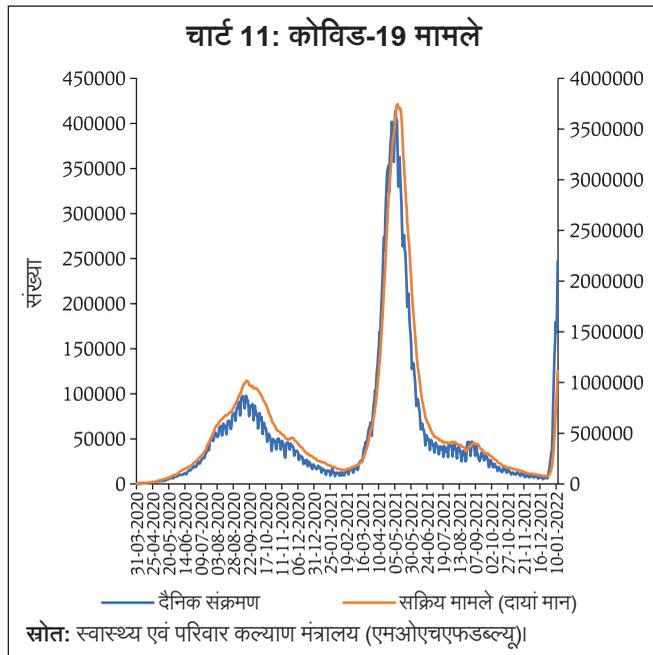
### III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी सुधार को तीसरी लहर (विशेषकर ओमीक्रॉन प्रसार) के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, गतिशीलता संकेतकों ने जनवरी में क्रमिक धीमापन प्रदर्शित किया। खुदरा और मनोरंजन गतिविधियों के लिए और कार्य-स्थलों के आस-पास गूगल गतिशीलता सूचकांक न्यूनतम संख्या से नीचे आ गए क्योंकि कार्यालयों ने तेजी से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपना ली (8 जनवरी, 2022 तक) (चार्ट 10ए)। ऐपल मोबिलिटी इंडेक्स सभी प्रमुख शहरों में

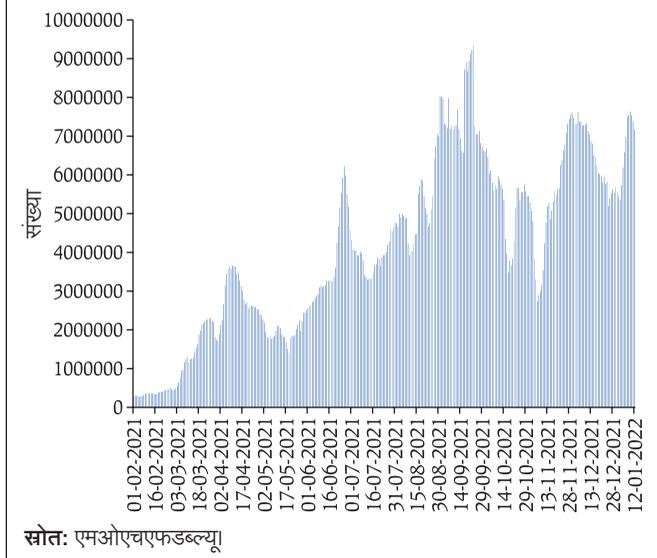


गिर गया, हालांकि यह अपने पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर रहा (चार्ट 10बी)। जनवरी से अब तक बिजली उत्पादन में तेज हुआ है, जो महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच गया है (चार्ट 10सी)।

13 जनवरी को दैनिक संक्रमण बढ़कर 2.71 लाख से अधिक हो गया, जो मई 2021 के मध्य के बाद से सबसे अधिक है, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या 15.5 लाख (चार्ट 11) थी। टीकाकरण के मोर्चे पर, भारत ने 13 जनवरी 2022 (चार्ट 12) तक 155.4 करोड़ टीका लगाकर सराहनीय प्रगति की है। 3 जनवरी 2022 से 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों/किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया है, जिसमें उन्हें 3.15 करोड़ खुराक दी गई हैं। इसके अलावा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए दो और टीकों को मंजूरी दी, जैसे - बायोलॉजिकल-ई का 'कॉर्बेवैक्स' और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 'कोवोवैक्स', ताकि वैश्विक महामारी के विरुद्ध सशक्त हुआ जा सके।



**चार्ट 12: दैनिक टीकाकरण का 7-दिवसीय चल औसत**

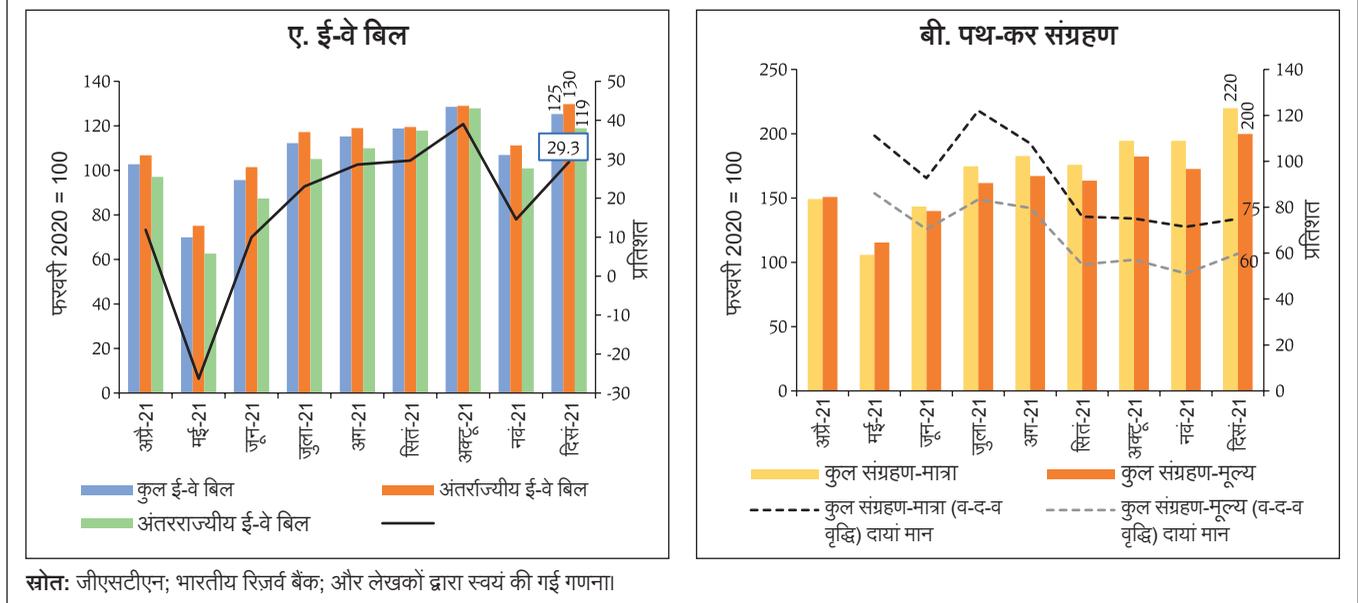


### कुल माँग

कुल माँग की स्थिति मजबूत बनी हुई है। ई-वे बिल निर्गम - माल दुलाई का एक संकेतक - दिसंबर में बढ़कर 7.2 करोड़ हो गया, जो इतिहास में दूसरी बार सर्वाधिक था (चार्ट 13ए)। यह जनवरी 2022 में माल और सेवा कर (जीएसटी) की अच्छी उगाही की संभावना का संकेत है। विनिर्माण और निर्माण में एक मजबूत बढ़त के कारण, राजमार्ग टोल उगाही में दिसंबर में माह-दर-माह 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 13बी)। दिसंबर में बिजली की खपत 4.5 फीसदी बढ़कर 110.3 बिलियन यूनिट हो गई।

दिसंबर 2021 में आवागमन में वृद्धि से ईंधन की खपत में वृद्धि हुई, पेट्रोल की खपत पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गई। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और डीजल की खपत में भी क्रमिक सुधार हुआ है, हालांकि एटीएफ अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 14ए) से नीचे है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में जनवरी 2021 के बाद से धीमी वृद्धि के उलट, जनवरी की शुरुआत में कमी के संकेत दिखाई दिए।

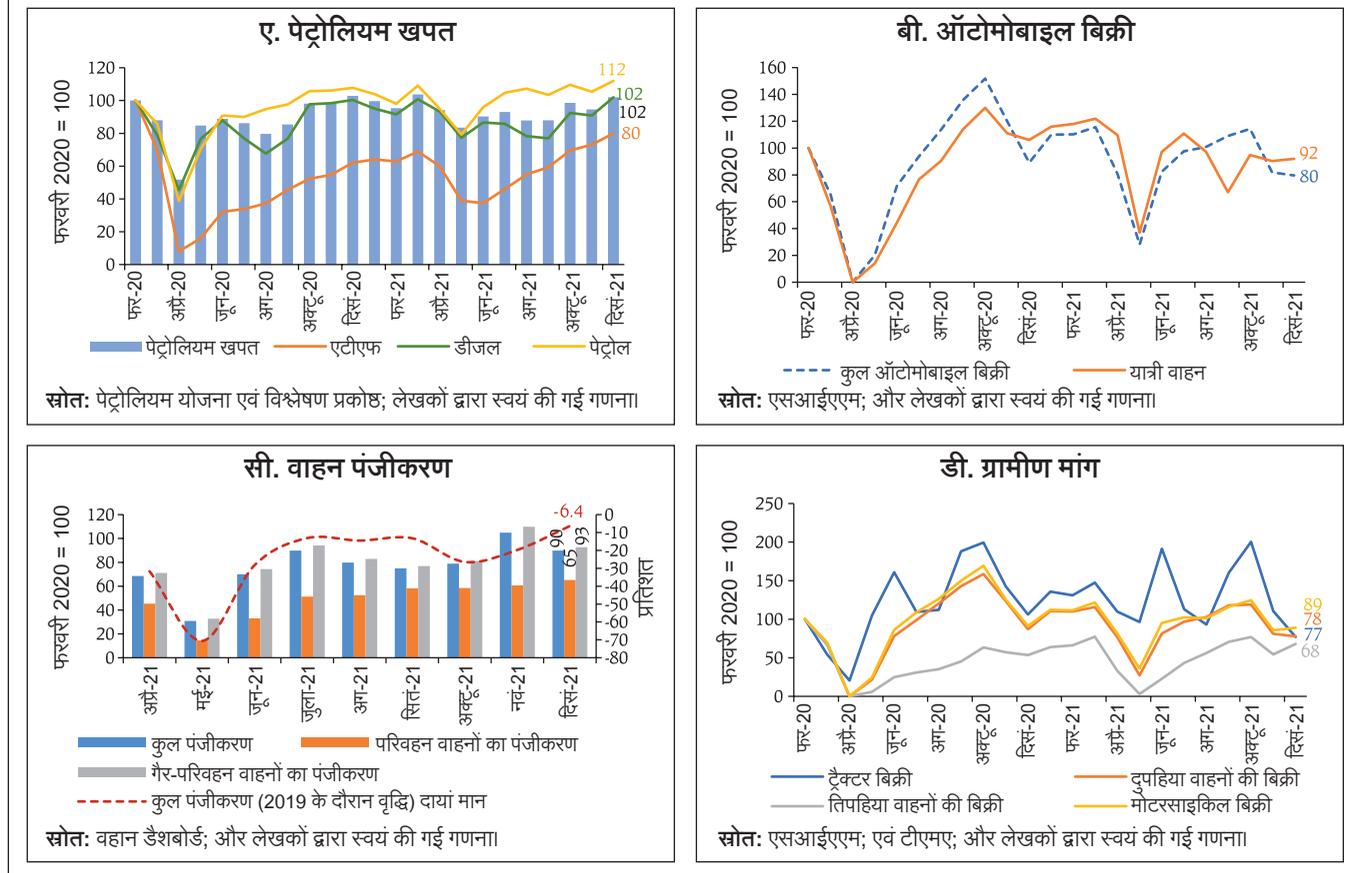
**चार्ट 13: ई-वे बिल और पथ-कर संग्रहण**



वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों (चार्ट 14बी) में मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर की कमी के कारण, दिसंबर 2021 में वाहन

पंजीकरण में व्यापक रूप से गिरावट आई थी। सर्वाधिक गिरावट दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में हुई जिसमें 19.9 प्रतिशत की

**चार्ट 14: परिवहन क्षेत्र के संकेतक**



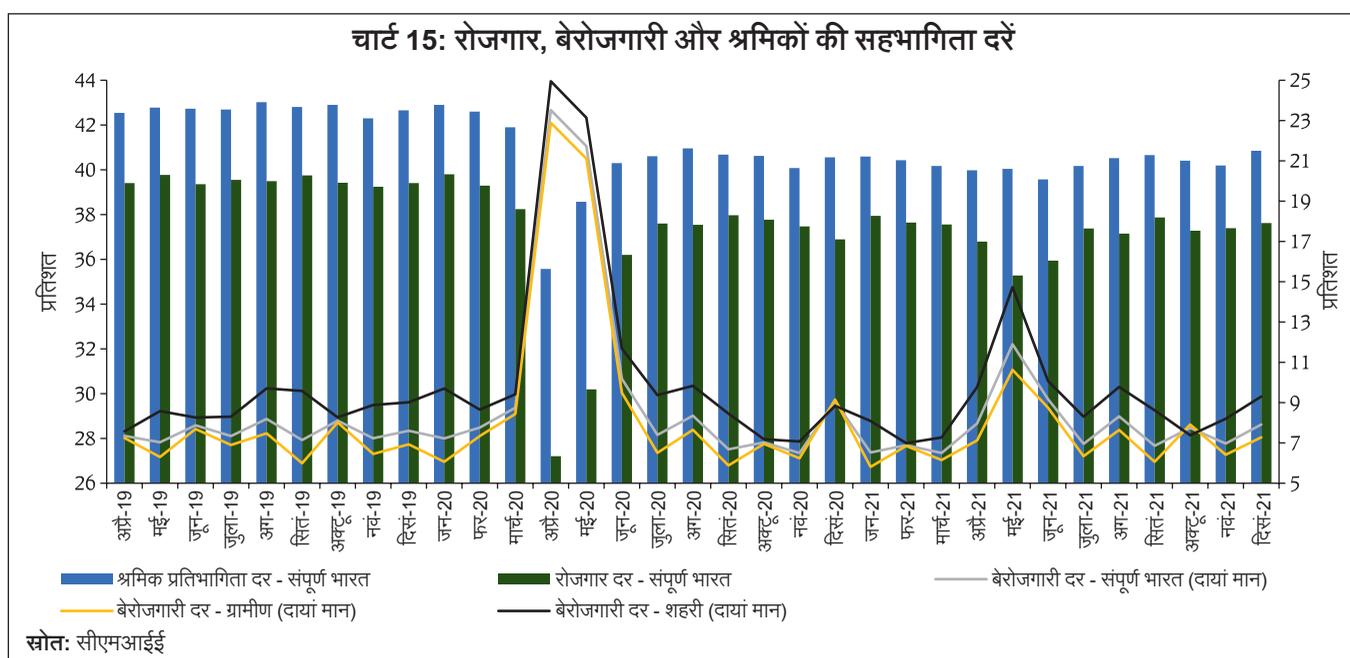
कमी देखी गई और इससे कुल पंजीकरण मात्रा में गिरावट आई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) के अनुसार, उच्च स्वामित्व-लागत, सुस्त ग्रामीण रुझान और ओमीक्रॉन के हालिया खतरे के कारण दिसंबर 2021 में बिक्री घटी (चार्ट 14सी)। हालांकि, माल-भाड़ा दरों में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई। ट्रैक्टर की बिक्री में 27.5 प्रतिशत की गिरावट, ग्रामीण मांग में गिरावट का संकेत है (चार्ट 14डी)।

उपभोक्ता का विश्वास लौटने के साथ ही, रेफनिटिव इपसॉस-प्राथमिक उपभोक्ता रुझान सूचकांक में एक महीने पहले की तुलना में दिसंबर में 2.6 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ। इससे व्यक्तिगत वित्त और निवेश के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई। वर्षात के दौरान समारोहों के लिए होटल बुकिंग में तेज वृद्धि हुई। कई स्थान और रिसॉर्ट पूरी तरह से भरे हुए थे<sup>2</sup> दिसंबर में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से पैकेटबंद खाद्य और अत्यावश्यक वस्तुओं की बिक्री के कारण थी<sup>3</sup> प्रधानमंत्री-किसान योजना की 10वीं किस्त के तहत ₹20,900 करोड़ निर्गत करने से ग्रामीण खपत बढ़ी। शीर्ष 7 शहरों

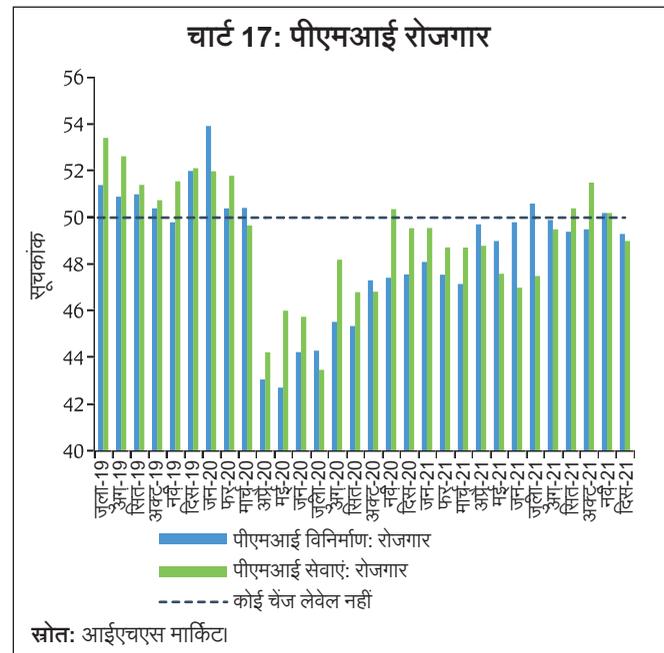
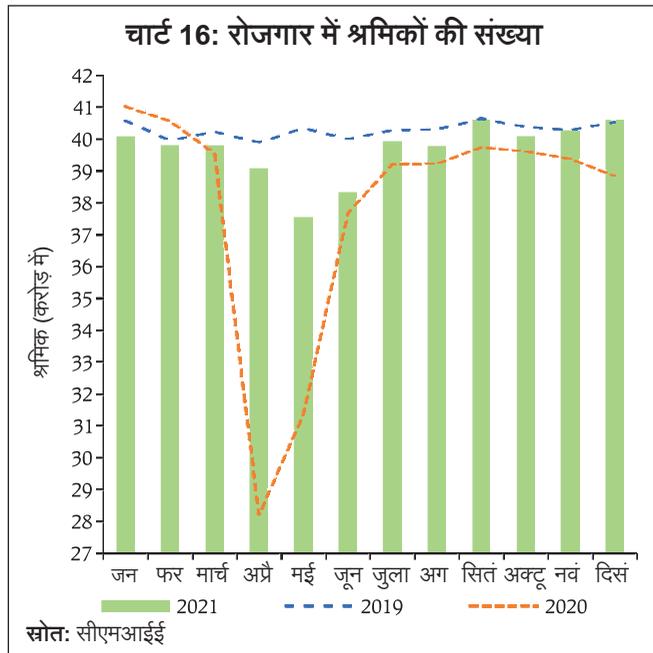
में, आवास की बिक्री में एक साल पहले की तुलना में 2021 में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका कारण दशकीय कम ब्याज दरें और बिल्डरों द्वारा आकर्षक छूट की पेशकश है<sup>4</sup>

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, दिसंबर में श्रम भागीदारी दर 40.9 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2020 के बाद सबसे अधिक है। रोजगार दर में भी 23 आधार अंकों का सुधार हुआ, हालांकि बेरोजगारी की दर एक महीने पहले के 7.0 प्रतिशत से दिसंबर में 7.9 प्रतिशत और खराब हो गई (चार्ट 15)। सीएमआईई द्वारा उद्योग-वार विश्लेषण इंगित करता है कि विनिर्माण, होटल, पर्यटन और शिक्षा में नौकरियां चली गईं, जबकि निर्माण, कृषि और खुदरा व्यापार में अधिक नौकरियां पैदा हुईं। सीएमआईई के रोजगार आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 में पहली बार नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या 2019 के स्तर (पूर्व-महामारी) को पार कर गई (चार्ट 16)।

स्टाफ प्रदाता-टीमलीज के अनुसार, ई-कॉमर्स और संबद्ध क्षेत्रों द्वारा नियुक्तियों में 2021 में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है<sup>5</sup>



<sup>2</sup> <https://www.livemint.com/companies/news/new-year-s-eve-bookings-give-solid-boost-to-hospitality-biz-11641237663084.html>  
<sup>3</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/packaged-foods-commodities-push-fmcg-sales-up-11/articleshow/88700894.cms>  
<sup>4</sup> <https://www.thehindubusinessline.com/economy/housing-sales-in-india-rise-71-y-o-y-reach-90-of-pre-covid-levels/article38098621.ece>  
<sup>5</sup> <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/e-commercehiring-surges-28-in-2021-teamlease/articleshow/88604278.cms>

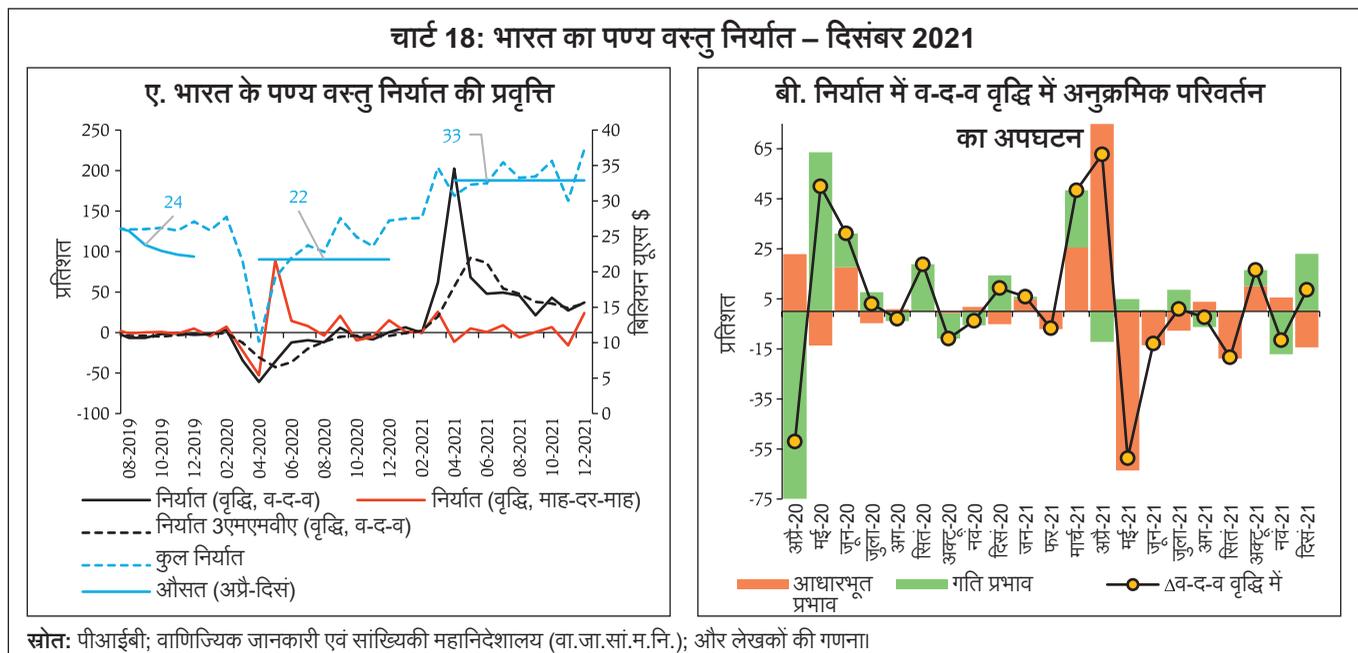


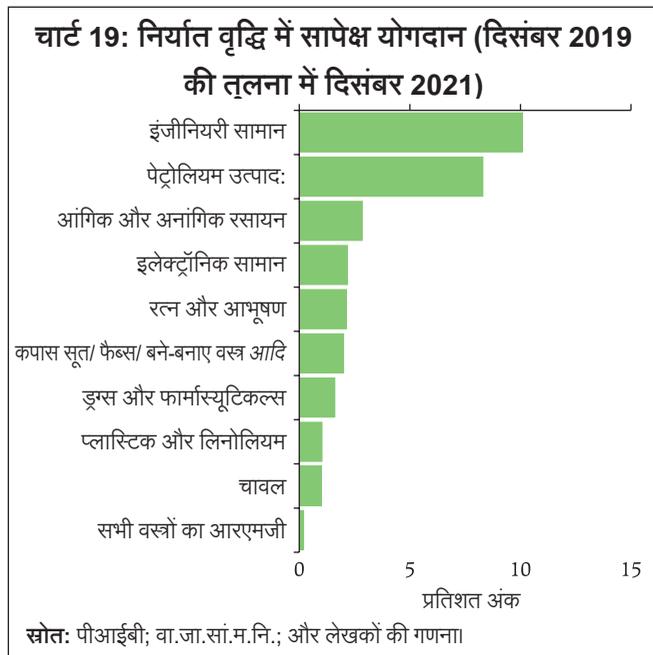
इसके विपरीत, क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के रोजगार खंड ने दर्शाया कि विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों के तहत रोजगार दिसंबर 2021 में संकुचित हो गया (चार्ट 17)।

दिसंबर में 25.9 प्रतिशत का क्रमिक सुधार दर्ज करते हुए, भारत का पण्य वस्तु निर्यात 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया और 2021-22 के लिए

निर्धारित लक्ष्य का 75 प्रतिशत हासिल कर लिया (चार्ट 18ए और 18बी)।

निर्यात वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें दस प्रमुख जिंस समूहों ने कुल निर्यात के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से के लिए अपने कोविड-पूर्व स्तर से ऊपर विस्तार दर्ज किया (चार्ट 19)। इंजीनियरी सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पोत-लदान के उच्च मूल्य से निर्यात



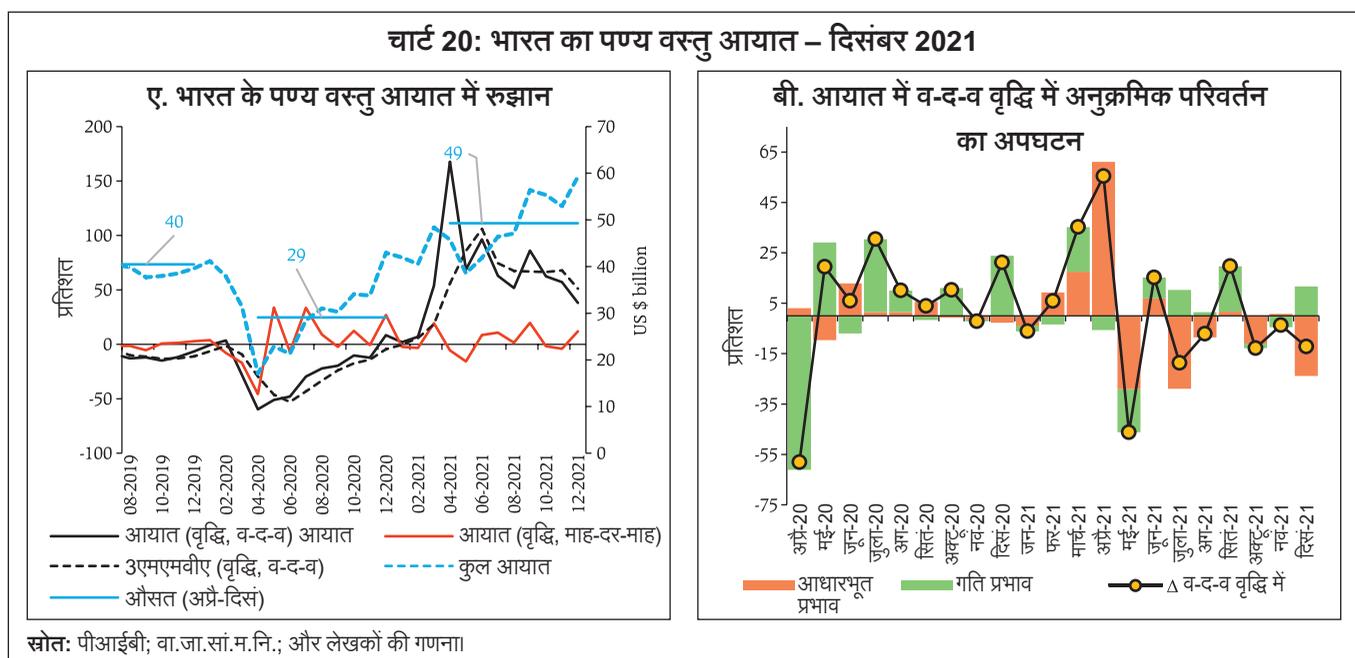


निष्पादन में सुधार आया। विशेष रूप से, वैश्विक धातु कीमतों में वृद्धि होने से इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 422.4 लाख कोविड-19 टीका खुराक के रिकॉर्ड निर्यात की सहायता से पूर्व-कोविड स्तर की तुलना में फार्मास्यूटिकल निर्यात में 23.5

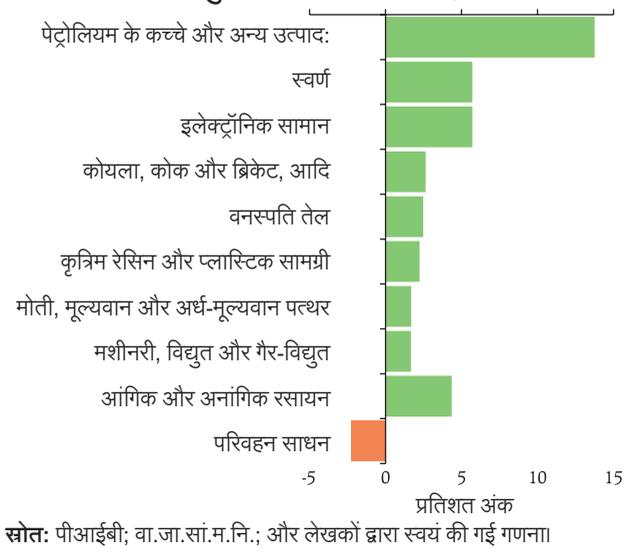
प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि निर्यात समूह का सबसे बड़ा घटक चावल है, जो महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में भी सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित करता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2022 में अनुमानित विश्व चावल व्यापार में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि भारत के चावल निर्यात के लिए अच्छी खबर है।

पण्य वस्तु आयात दिसंबर 2021 में अपने उच्चतम स्तर 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो लगातार चौथे महीने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर बना रहा और घरेलू मांग की मजबूत अंतर्निहित संवेग को दर्शाता है (चार्ट 20ए और 20बी)।

सुदृढ़ आयात मांग पेट्रोलियम उत्पादों, सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से प्रेरित थी (चार्ट 21)। इसके अलावा, दस प्रमुख जिंस समूहों में से नौ 70 प्रतिशत से अधिक आयात के लिए उत्तरदायी थे और उन्होंने कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में अधिक विस्तार दर्ज किया, जो व्यापक-आधारित मांग में वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2021 में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सोने का आयात पूर्व-सीओवीआईडी अवधि की तुलना में 91.7 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 720.3 टन के साथ भारत पहले ही पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक आयात मात्रा का 88.1 प्रतिशत आयात कर चुका है।



**चार्ट 21: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान (दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2021)**

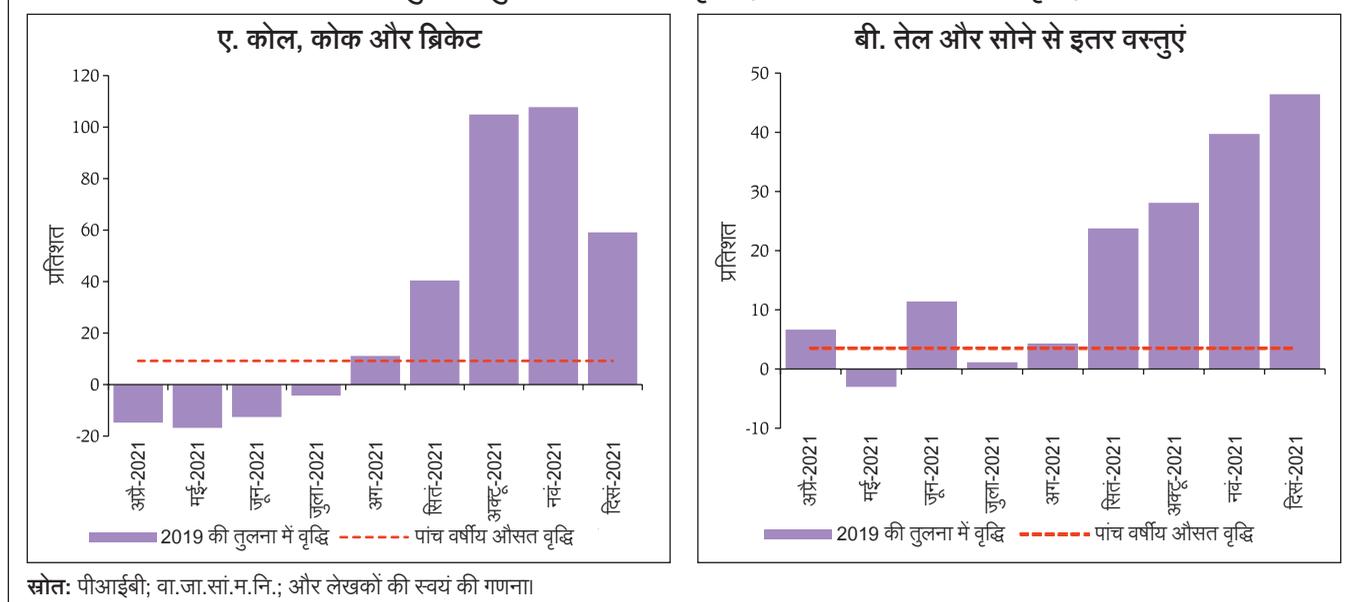


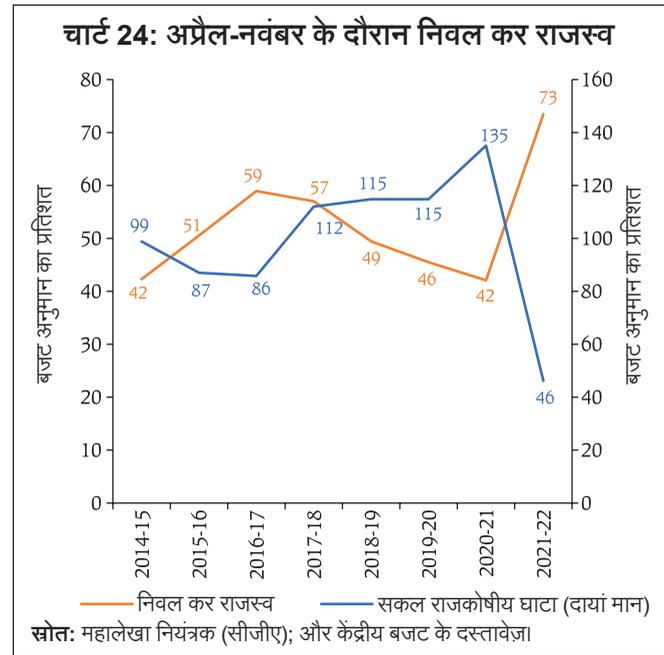
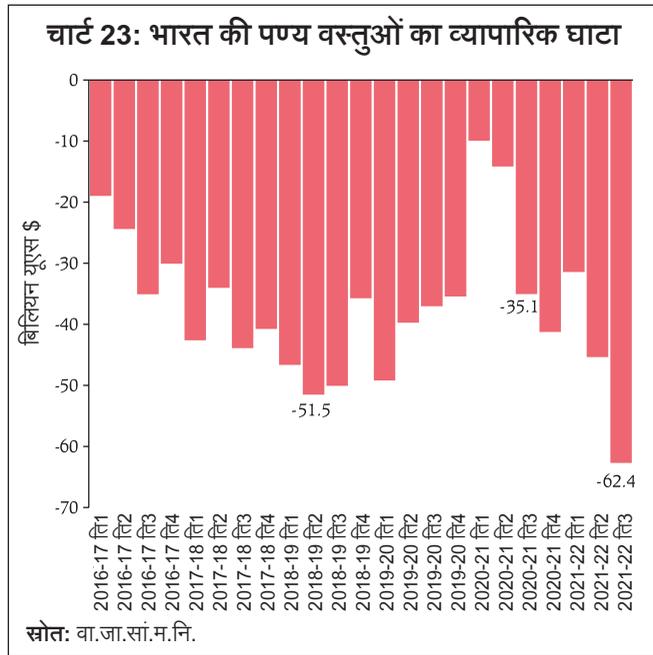
दिसंबर 2021 के दौरान कोयले, कोक और ब्रिकेट के आयात में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 22ए)। समग्र रूप से तेल और सोने से इतर वस्तुओं के आयात में दिसंबर में लगातार सातवें महीने महामारी-पूर्व स्तर पर मजबूत वृद्धि बनी रही (चार्ट 22बी)।

नवंबर 2021 में 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च मासिक व्यापार घाटे के बाद, दिसंबर 2021 में व्यापार घाटा कम होकर 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तिमाही आधार पर, 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा 62.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। (चार्ट 23)।

केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार जारी रहा, जिसमें निवल कर राजस्व, बजट अनुमान (बीई) के 73.5 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था और सकल राजकोषीय घाटे में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत तक की कमी आ गई, जिसकी तुलना में पहले पांच वर्षों का औसत क्रमशः 50.6 प्रतिशत और 112.5 प्रतिशत था (चार्ट 24)। व्यय के पहलू पर, पूंजीगत व्यय में 13.5 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि राजस्व व्यय में 2020-21 की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने बजटीय पूंजीगत व्यय के 68.3 प्रतिशत हिस्से का उपयोग करने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई। बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार, हालांकि अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों प्रवृत्ति से कम हैं।

**चार्ट 22: प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि (2019 के स्तर से अधिक वृद्धि)**

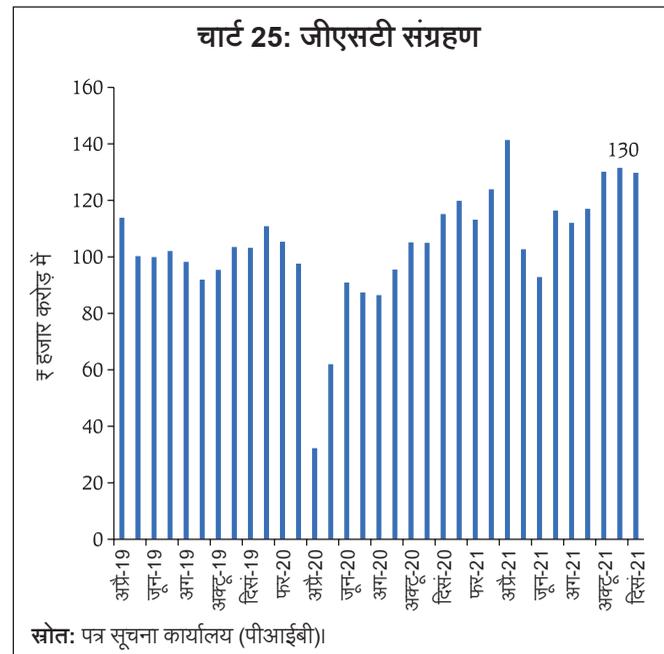




यदि 2021-22 के बजट अनुमान और अनुदान की दो अनुपूरक मांगों में निहित व्यय प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, तो कुल मांग को बढ़ावा देते हुए ब्याज भुगतान घटाकर राजस्व व्यय और प्रमुख सब्सिडी (सरकार के अंतिम उपभोग व्यय का एक संकेतक) 2020-21 की तुलना में 29.0 प्रतिशत (2019-20 की तुलना में 70.3 प्रतिशत) तक बढ़ सकता है। बढ़े हुए व्यय की आंशिक रूप से कर संग्रह में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को उच्चतर सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद से भी लाभ होगा, जो कि 2021-22 के बजट अनुमानों के लिए की गई ₹222.87 लाख करोड़ की पूर्वधारणा की तुलना में ₹232.15 लाख करोड़ है।

जीएसटी संग्रहण के अंतर्गत दिसंबर 2021 में 12.7 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि दर्ज की (चार्ट 25)। 2021-22 की तीसरी तिमाही में ₹3.9 लाख करोड़ का तिमाही जीएसटी संग्रह हुआ, जो कि जीएसटी की शुरुआत के बाद से अभी तक का उच्चतम दर्ज संग्रह है। यह अनुपालन में सुधार के लिए विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम है और संभवतः जीएसटी व्यवस्था होने के अंतर्निहित लाभों को प्रदर्शित करेगा।

राज्य वित्त ने महामारी-पूर्व के स्तर से अधिक राजस्व प्राप्ति के साथ महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राज्यों की कर और कर-रहित प्राप्तियों में क्रमशः 29.2 प्रतिशत और 53.8 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों के सभी प्रमुख कर शीर्षों ने 2019-20 के स्तर को पार कर लिया



है और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान उच्च वृद्धि आयी है। विशेष रूप से, राज्यों के जीएसटी राजस्व और बिक्री कर संग्रह में क्रमशः 35.2 प्रतिशत और 37.3 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2021 तक राज्यों ने 2018-19 के बाद से पिछली प्रवृत्ति की तुलना में अपनी बजटीय राजस्व प्राप्तियों का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा संग्रहित किया है (चार्ट 26ए)।

व्यय में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 26बी)। व्यय की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है, जो अप्रैल-नवंबर 2021 में राज्यों के पूंजीगत व्यय में 67.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए परिलक्षित होता है (चार्ट 26सी)। पूंजीगत व्यय पर जोर एक स्थायी विकास पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है। कुल मिलाकर, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा अधिकांश

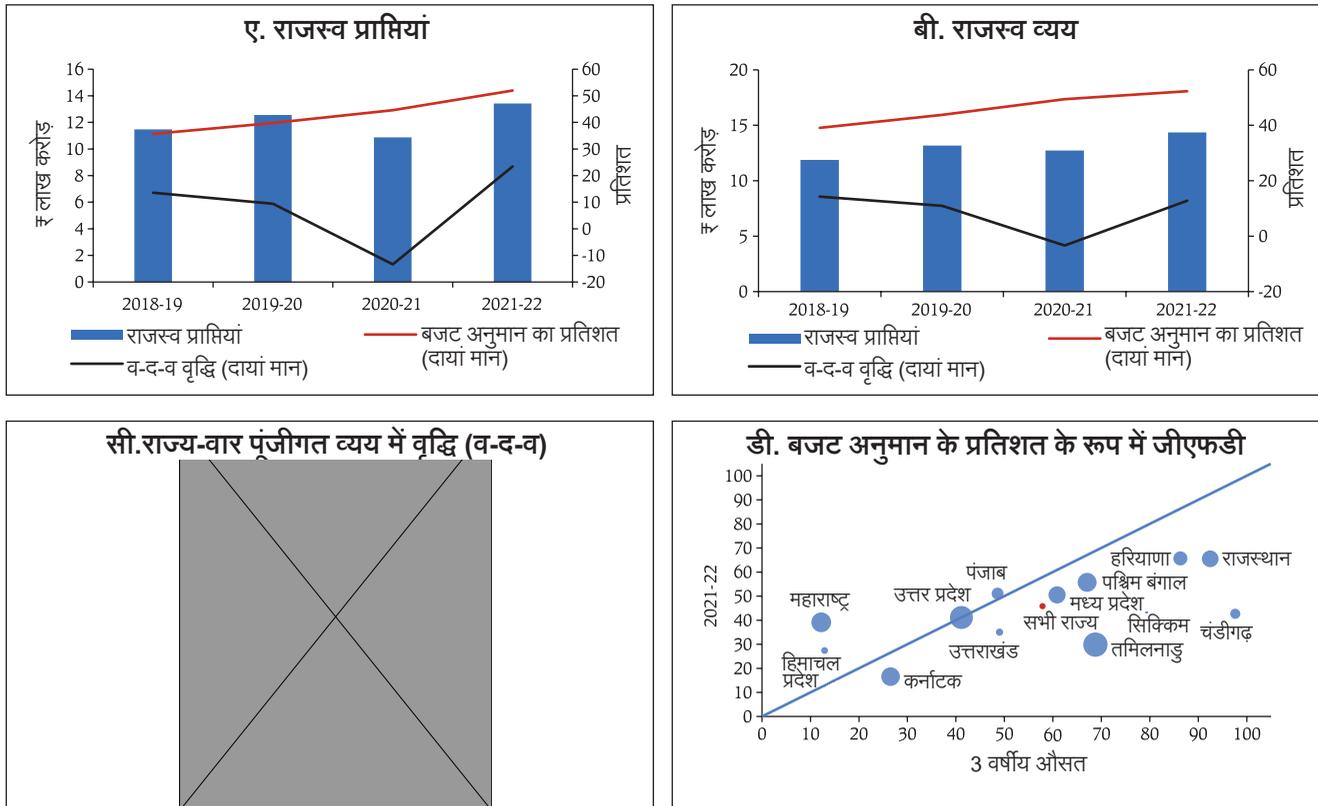
राज्यों के बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में तेजी से कम हुआ है, जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है (चार्ट 26डी)।

**समग्र आपूर्ति**

आपूर्ति पक्ष पर, मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई कुल आपूर्ति 2021-22 में 8.6 प्रतिशत<sup>6</sup> की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 6.2 प्रतिशत के संकुचन पर थी। कृषि में सुदृढ़ वृद्धि और साथ-साथ उद्योग में और सेवा क्षेत्र के कई घटकों में सुधार के साथ से जीवीए वृद्धि में तेजी आयी यद्यपि यह अनुकूल आधार पर थी (चार्ट 27)।

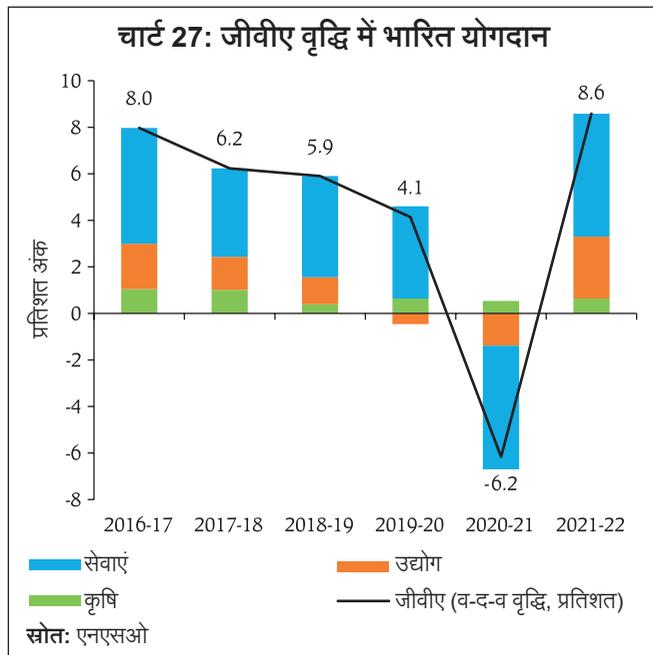
फिर से भरे हुए जलाशय स्तर (चार्ट 28ए) और स्थानिक और अस्थायी रूप से अच्छी तरह से वितरित उत्तर-पूर्व (एनई) मानसून वर्षा द्वारा समर्थित, अब तक 664.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रबी बुवाई के तहत कवर किया गया है, जो पूरे मौसम के

**चार्ट 26: राज्य वित्त (अप्रैल-नवंबर 2021-22)**



**टिप्पणी:** सभी डेटा 18 राज्यों से संबंधित है, जिसके लिए नवंबर 2021 तक का डेटा उपलब्ध है।  
**स्रोत:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

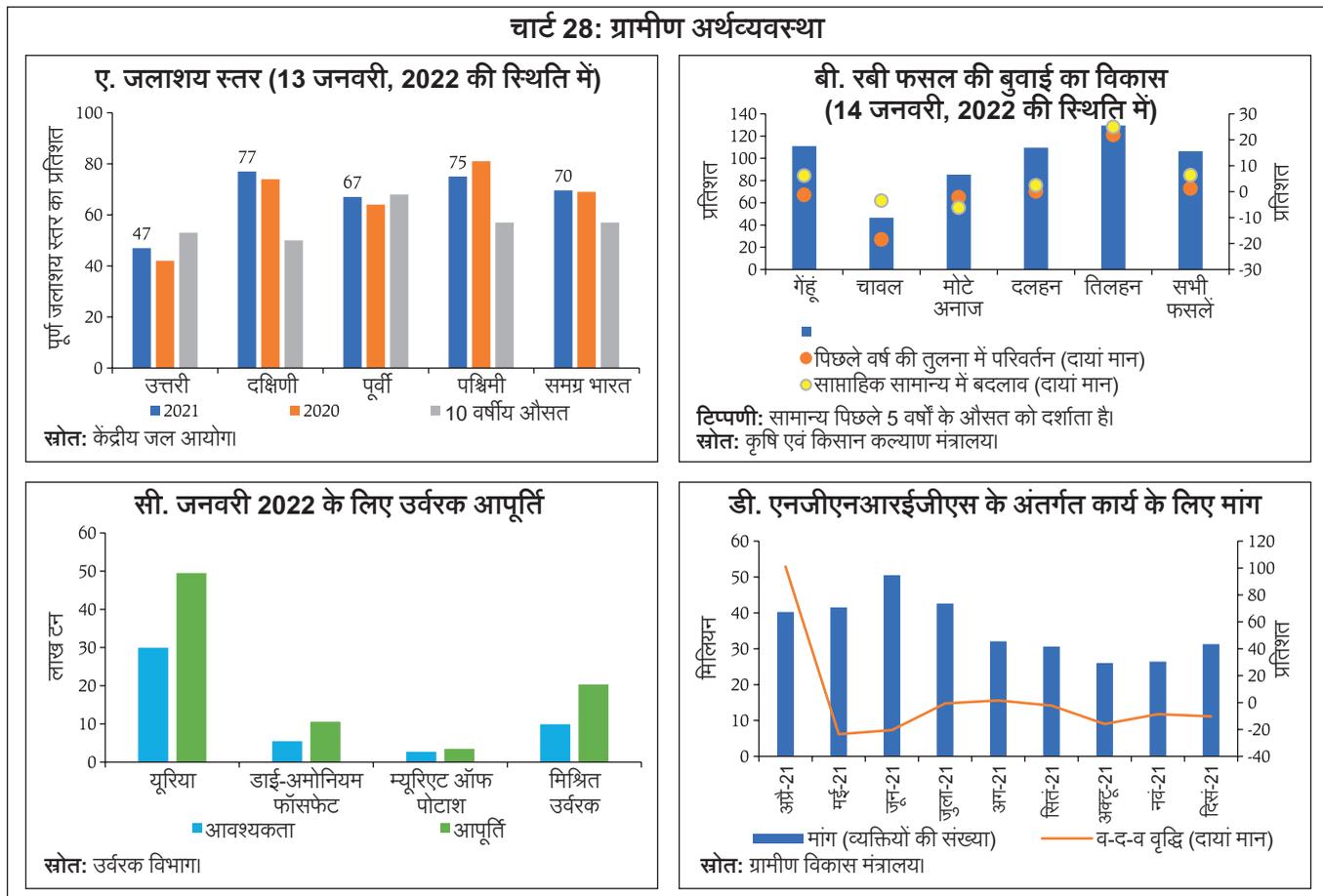
<sup>6</sup> यह एनएसओ द्वारा 7 जनवरी, 2022 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।



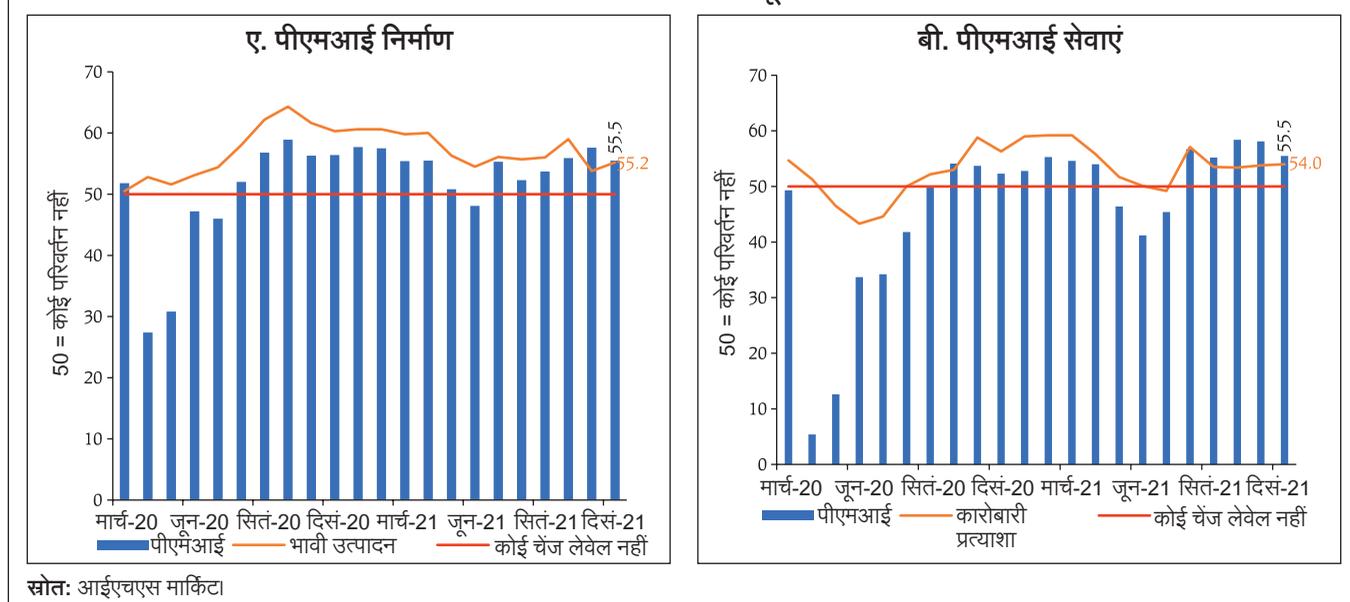
सामान्य रबी क्षेत्रफल का 106.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से, सफेद सरसों और सरसों के तिलहन का क्षेत्रफल पूरे मौसम के सामान्य

क्षेत्र से 46.9 प्रतिशत अधिक रहा, जो सरकार द्वारा मूल्य आश्वासन के रूप में दिए गए प्रोत्साहन को दर्शाता है (चार्ट 28बी)। 14 जनवरी 2022 तक, तिलहन के तहत बोए जाने वाले क्षेत्र में पिछले वर्ष (21.8 प्रतिशत) की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गेहूं, चावल और मोटे अनाज के बुवाई क्षेत्रफल में कमी आयी। प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति के पिछले वर्ष के स्तर से कम रहने के बावजूद, (12 जनवरी, 2022 तक) मासिक उपलब्धता आवश्यक स्तरों की तुलना में अधिक थी (चार्ट 28सी)। ग्रामीण पशुभूमि में चल रही रबी की बुवाई से उत्पन्न रोजगार को दर्शाते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग दिसंबर 2021 में लगातार चौथे महीने में घट गई (चार्ट 28डी)।

12 जनवरी की स्थिति के अनुसार, चावल की 37.3 मिलियन टन (खरीफ विपणन मौसम 2021-22) संचयी खरीद पिछले वर्ष (36.3 मिलियन टन) के स्तर से अधिक थी। त्रैमासिक



**चार्ट 29: क्रय प्रबंधक सूचकांक**

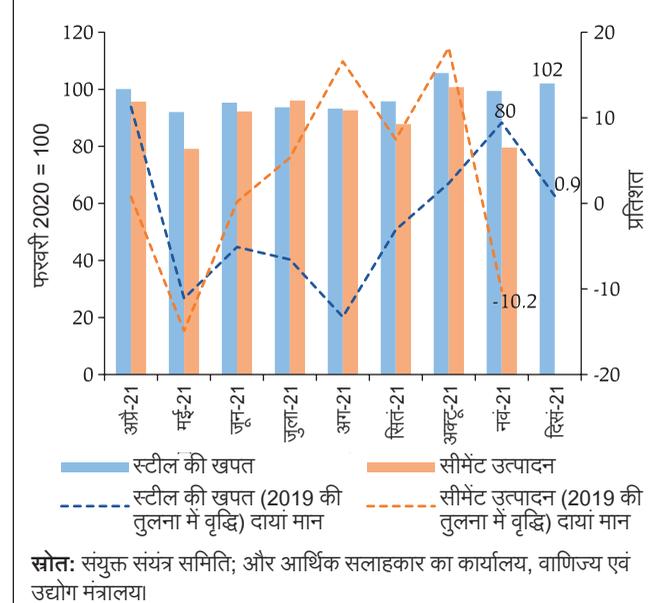


सुरक्षित भंडार मानदंडों (जनवरी-मार्च) के अनुसार, चावल और गेहूं दोनों के लिए पर्याप्त स्टॉक स्तर (क्रमशः 7.1 और 2.4 गुना) बना रहा। 20 दिसंबर, 2021 को मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए नीतिगत उपायों के रूप में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक साल की अवधि के लिए सभी पण्य बाजारों में धान (गैर-बासमती), गेहूं, चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों के बीज और ताड़ के कच्चे तेल में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी।

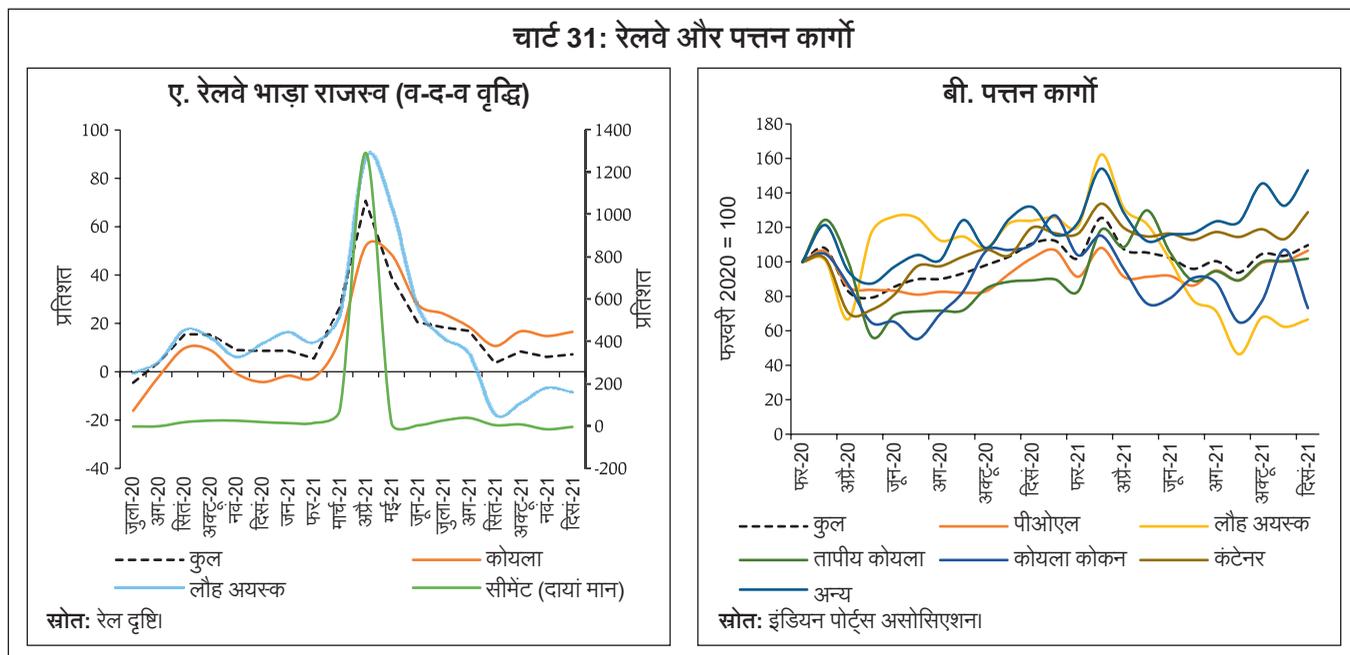
औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में विस्तार बना रहा और दिसंबर 2021 में 55.5 पर रहा। हालांकि, उत्पादन में गिरावट, खरीद के स्टॉक और नए ऑर्डर के कारण नवंबर में यह 57.6 के स्तर से कम हो गया। दिसंबर में भारत का कोयला उत्पादन बढ़कर 74.8 मिलियन टन हो गया, जो इसके महामारी-पूर्व के स्तर से 6.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र का पीएमआई लगातार पांचवें महीने विस्तार दर्ज करते हुए दिसंबर में 55.5 रहा। सेवाओं के लिए कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) नवंबर 2021 में 53.8 से बढ़ कर दिसंबर 2021 में 54.0 हो गया (चार्ट 29)।

हालिया महीनों में निर्माण गतिविधि में कमी आयी है, जैसा कि इसके अनुकूल संकेतकों के निष्पादन से स्पष्ट है। दिसंबर में इस्पात की खपत में गिरावट जारी रही, हालांकि इसका मुख्य कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम मांग था। नवंबर 2021 में पिछले दस महीनों में पहली बार सीमेंट उत्पादन में कमी आयी है, जो मांग में कमी को दर्शाता है (चार्ट 30)।

**चार्ट 30: निर्माण क्षेत्र के संकेतक**



**चार्ट 31: रेलवे और पत्तन कार्गो**



सेवा क्षेत्र में, रेलवे माल यातायात दिसंबर में बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गया, जो पिछले महीने में 6.3 प्रतिशत थी (चार्ट 31ए)। जैसे ही पोत-परिवहन बाधाएं और कंटेनर की कमी विश्व स्तर पर कम हुई, दिसंबर 2021 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात क्रमिक रूप से बढ़ा। एक साल पहले, लौह अयस्क और कोकिंग कोल कार्गो में गिरावट के कारण कार्गो यातायात में 0.8 प्रतिशत की मामूली कमी आयी थी (चार्ट 31बी)।

विमानन क्षेत्र में यात्री और कार्गो यातायात, दोनों ने अगस्त 2021 के बाद से धीरे-धीरे सुधार का प्रदर्शन किया है, नवंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कार्गो भाड़ा, दोनों सामान्य हो गए हैं। त्योहारी मौसम के दौरान यात्रा करने से यात्री यातायात में भी तेजी आयी। ओमीक्रॉन के हालिया खतरे के मद्देनजर, नए यात्रा दिशानिर्देश इस क्षेत्र के विकास में बाधा बन सकते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में दैनिक घरेलू हवाई अड्डे पर यात्रियों

की संख्या<sup>7</sup>, औसतन 6.4 लाख प्रति दिन थी, जो दिसंबर में इसी सप्ताह की तुलना में 7.9 प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की संख्या में भी क्रमिक रूप से 7.2 प्रतिशत की गिरावट आयी है। कार्गो क्षेत्र ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए क्रमशः 23.7 और 21.6 प्रतिशत के दोहरे अंकों में संकुचन दर्ज किया, क्योंकि हवाई कंपनियों ने कोविड-19 संक्रमणों की बढ़ती संख्या के कारण उड़ानों को रद्द या पुनर्निर्धारित किया।

व्यापार, होटल, परिवहन संचार और जीएसटी ई-वे बिल के निष्पादन में सुधार हुआ (सारणी 2)। डिजिटलीकरण की तीव्र गति और फर्मों द्वारा उच्च विवेकगत व्यय द्वारा 2021-22 की तीसरी तिमाही में आईटी क्षेत्र का बेहतर निष्पादन हुआ था<sup>8</sup>

<sup>7</sup> इसमें प्रस्थान करने वाले और आने वाले, दोनों यात्री शामिल हैं।

<sup>8</sup> [https://www.business-standard.com/article/companies/infosys-to-hcl-tech-it-firms-to-see-strong-q3-despite-seasonal-quirks-122010400072\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/companies/infosys-to-hcl-tech-it-firms-to-see-strong-q3-despite-seasonal-quirks-122010400072_1.html)

**सारणी 2: उच्च आवृत्ति वाले संकेतक- सेवा क्षेत्र**

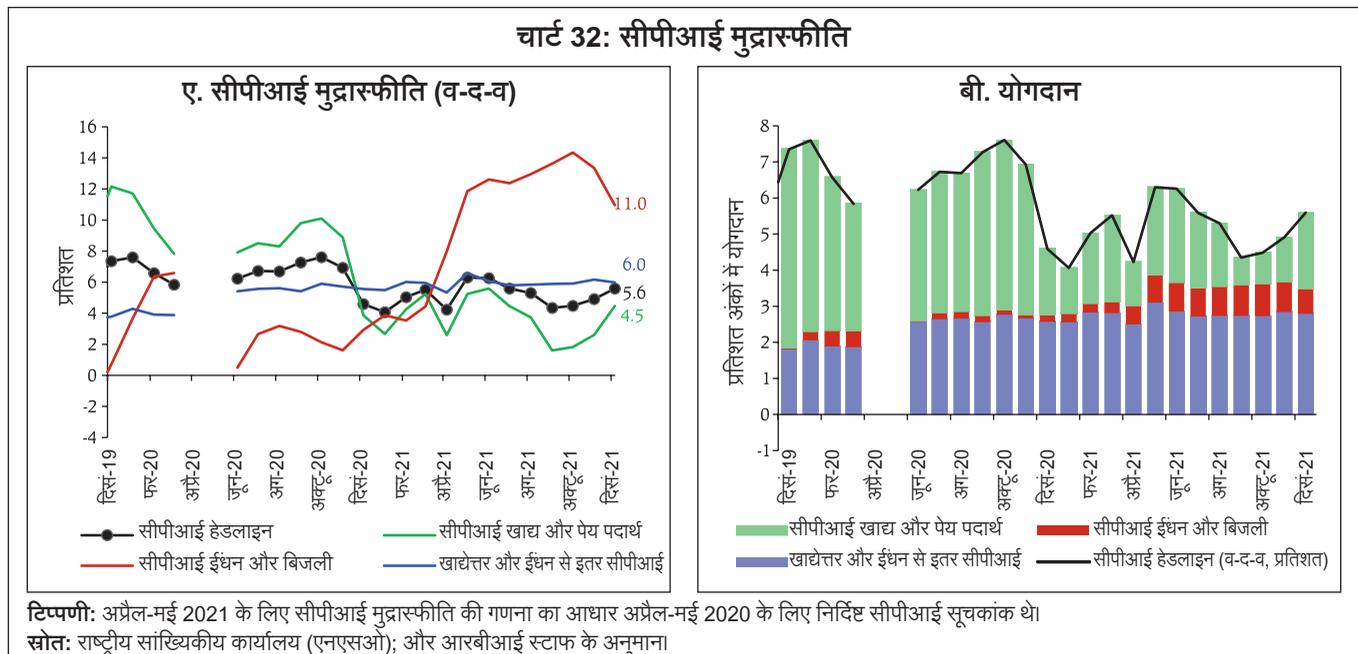
उच्च आवृत्ति वाले संकेतक- सेवा क्षेत्र वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)							2019 की तुलना में वृद्धि					
क्षेत्र	संकेतक	अग-21	सितं-21	अक्तू-21	नव-21	दिसं-21	अग 21/ अग 19	सितं 21/ सितं 19	अक्तू 21/ अक्तू 19	नव 21/ नव 19	दिसं 21/ दिसं 19	
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	22.8	-25.6	-16.7	-14.8	-1.5	
	दुपहिया वाहनों की बिक्री	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-12.1	-7.7	-12.3	-25.5	-4.2	
ग्रामीण मांग	तिपहिया वाहनों की बिक्री	59.7	53.8	19.1	-6.6	25.1	-60.5	-56.0	-52.6	-59.7	-47.7	
	ट्रैक्टर की बिक्री	-17.0	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	45.0	9.3	8.2	17.2	3.8	
व्यापार, रेस्तरां, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	24.5			0.9		0.6			-0.3		
	रेलवे माल यातायात	16.9	3.6	8.4	6.1	7.2	21.5	19.7	25.1	15.6	16.5	
	पोट कार्गो यातायात	11.5	0.5	6.3	-0.2	-0.8	-0.1	-1.4	5.3	2.7	3.5	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	35.7	10.1	6.7	-1.7		-13.1	-11.8	-10.0	-11.4		
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	25.8	18.1	23.8	11.7		-5.5	2.0	8.4	-5.0		
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	132.6	76.5	68.7	65.5		-43.8	-38.4	-27.0	-17.6		
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	119.2	155.9	162.9	140.2		-77.5	-68.9	-61.0	-58.6		
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	33.3	18.3	14.5	5.9	11.6	28.6	29.6	39.0	14.5	29.3	
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर्राज्यीय)	30.8	15.6	14.1	7.3	13.4	32.7	33.0	40.7	17.6	33.0	
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	37.2	22.3	15.1	3.9	8.9	22.9	25.0	36.7	10.1	24.0	
	पर्यटकों का आगमन	329.9	278.8	337.0	255.0		-89.4	-85.8	-80.8	-76.9		
	निर्माण	इस्पात की खपत	-2.2	-3.2	-3.8	-7.7	-14.1	-13.3	-3.1	2.4	9.4	0.9
		सीमेंट उत्पादन	36.3	10.8	14.5	-3.2		16.6	7.5	18.3	-10.2	
पीएमआई सूचकांक	विनिर्माण	52.3	53.7	55.9	57.6	55.5						
	सेवाएं	56.7	55.2	58.4	58.1	55.5						

स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी डेटा; आईएचएस मार्किट; एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त संयंत्र समिति।

**मुद्रास्फीति**

दिसंबर 2021 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) एक महीने पहले के 4.9 प्रतिशत से

बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट 32ए)। लगभग एक प्रतिशत अंक के एक बड़े प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव (एक वर्ष पहले कीमतों में माह-दर-माह परिवर्तन) के माध्यम से लगभग 35 आधार अंकों द्वारा



गति में एक स्वागत योग्य गिरावट (चालू महीने में कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) की भरपाई की गई। जिसके परिणामस्वरूप नवंबर और दिसंबर के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 70 आधार अंकों की वृद्धि हुई। सीपीआई खाद्य समूह, विशेष रूप से सब्जियां, हेडलाइन सीपीआई गति में गिरावट का प्रमुख चालक था। इसे प्रतिकूल आधारभूत-प्रभावों का भी सामना करना पड़ा।

दिसंबर में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई जो कि नवंबर में 2.6 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण लगभग 2.7 प्रतिशत अंकों का प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव था। अनाज, अंडे, दूध और तैयार खाद्यों की मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। दूसरी ओर मांस और मछली, तेल और वसा, फल, दालें, चीनी और मिष्ठान्न, मसाले और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति सामान्य हुई। दिसंबर में सब्जियों की कीमतों की अवस्फीति में काफी कमी आयी।

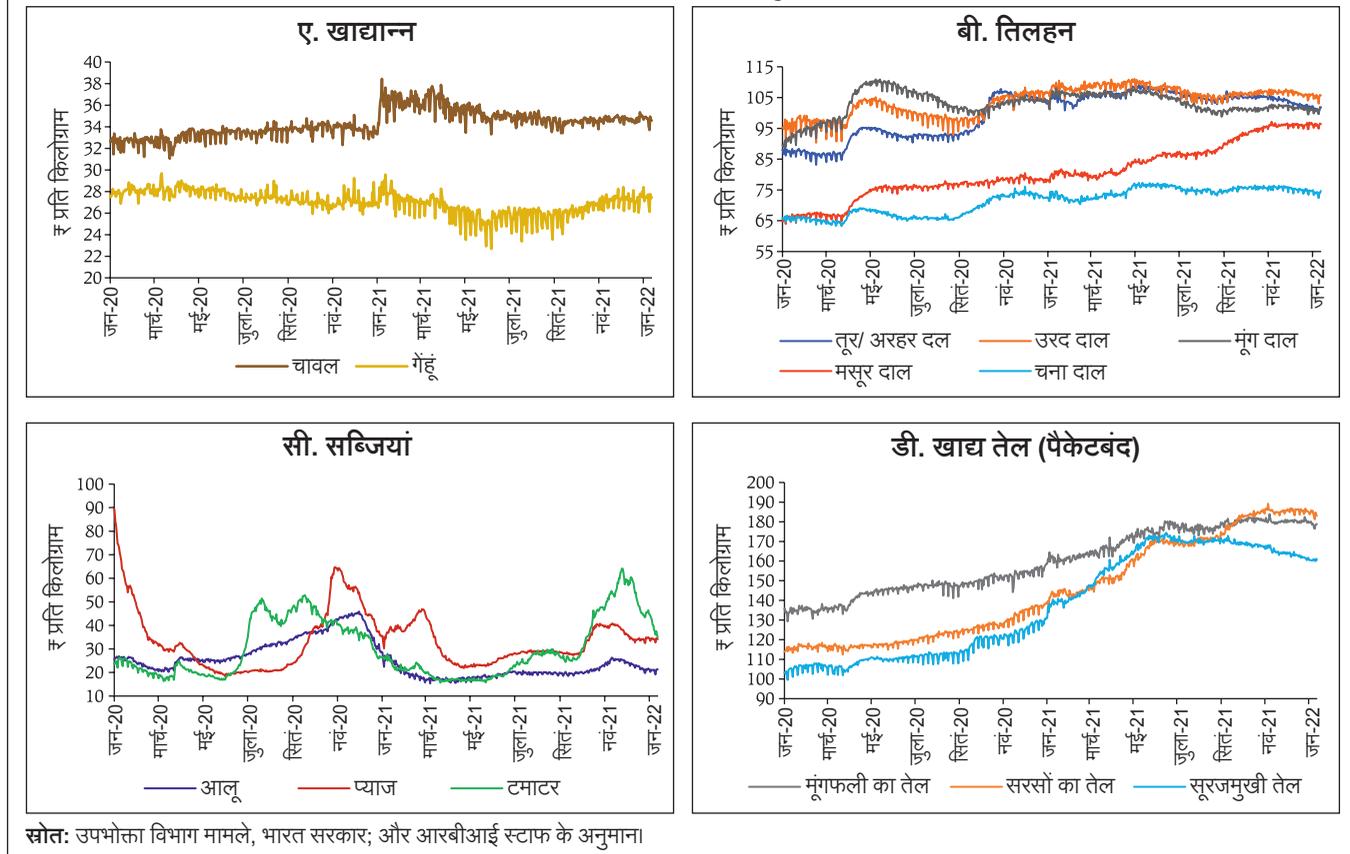
मुख्य रूप से एलपीजी, मिट्टी के तेल व जलाऊ लकड़ी और चिप के कारण ईंधन मुद्रास्फीति नवंबर में 13.3 प्रतिशत से

दिसंबर में 11.0 प्रतिशत हो गई। दिसंबर में बिजली की कीमतों में गिरावट जारी रही। सीपीआई ईंधन (सीपीआई समूह में 6.84 प्रतिशत का भार) ने दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 32बी)।

खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई मुद्रास्फीति या मूल मुद्रास्फीति दिसंबर में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि पर बनी रही, हालांकि नवंबर 2021 में देखी गई 6.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से कुछ कमी थी (चार्ट 32ए)। जबकि कपड़े और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, शिक्षा, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप-समूहों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, वहीं पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, और मनोरंजन और कौतुक में मुद्रास्फीति में कमी आयी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के जनवरी के लिए अब तक (1-12 जनवरी, 2022) के उच्च आवृत्ति डेटा प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में व्यापक आधारित गिरावट का संकेत देते हैं। अनाज की

चार्ट 33: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें



## सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जन-21	दिसं-21	जन-22 ^	दिसं-21	जन-22
पेट्रोल	₹/लीटर	87.57	102.93	102.87	-2.5	-0.1
डीजल	₹/लीटर	78.97	90.51	90.51	-1.3	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी प्राप्त)	₹/लीटर	23.21	38.68	38.68	-2.1	0.0
एलपीजी (सब्सिडी के बिना)	₹/सिलेंडर	704.63	910.13	910.13	0.0	0.0

^: 1-12 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए।

**टिप्पणी:** मिट्टी के तेल की कीमत के अलावा अन्य कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी-प्राप्त कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

**स्रोत:** आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, जबकि दालों के साथ-साथ खाद्य तेलों की कीमतों में व्यापक आधार वाली गिरावट दर्ज की गई। आलू, प्याज और विशेष रूप से टमाटर की कीमतों में मौसमी कीमतों में सुधार देखा गया (चार्ट 33)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य जनवरी में अब तक अपरिवर्तित रहे। जनवरी के पहले अर्धांश में एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतें भी स्थिर रहीं (सारणी 3)।

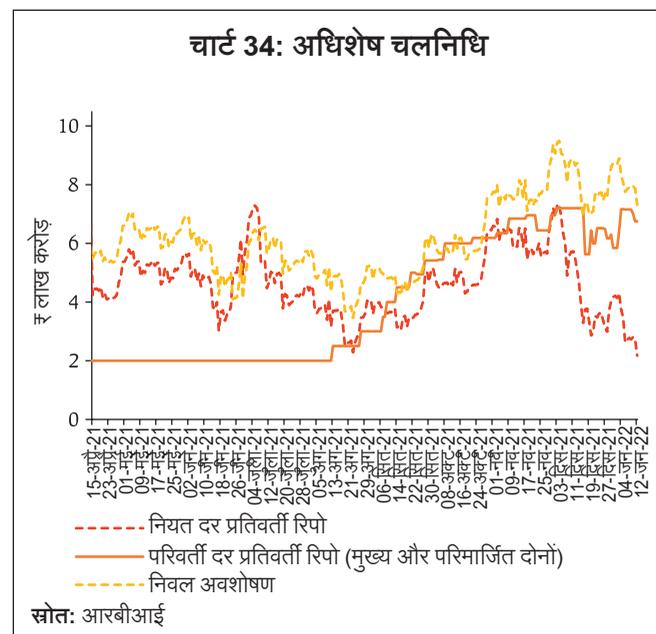
दिसंबर में निविष्टि लागत दबाव में कुछ कमी आयी, जैसा कि पीएमआई में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में परिलक्षित होता है। विनिर्माण और सेवाओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हुई।

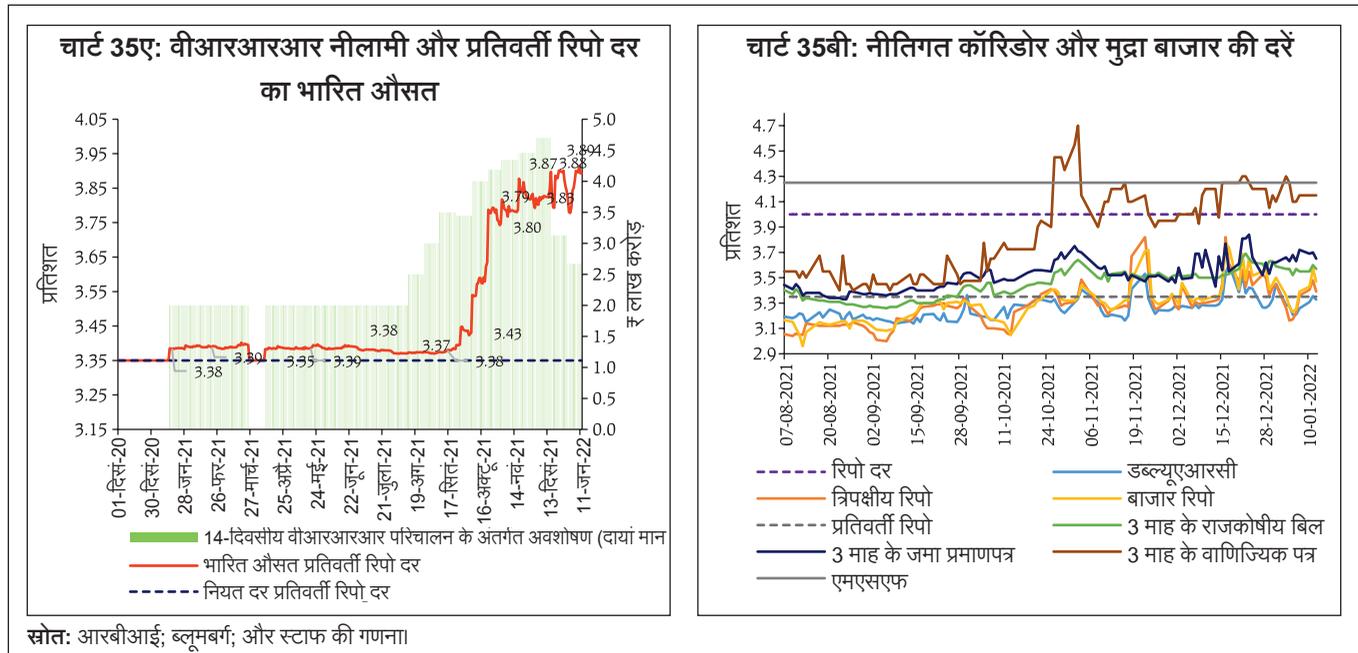
#### IV. वित्तीय स्थितियां

समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि के बीच समुत्थान बनाए रखते हुए, रिजर्व बैंक ने एमपीसी के समायोजनकारी नीतिगत रुख के अनुरूप पर्याप्त चलनिधि अधिशेष बनाए रखते हुए सक्रिय चलनिधि प्रबंधन किया। साथ ही, अधिशेष चलनिधि को नियत दर पर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रिपो अवधि से लंबी परिपक्वता की परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों में स्थानांतरित करके चलनिधि अधिशेष का पुनर्संतुलन जारी रखा

गया था। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक ने महीने की दूसरे अर्धांश में, यानी 17 दिसंबर और 31 दिसंबर को क्रमशः ₹6.5 लाख करोड़ और ₹7.5 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी आयोजित की। अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रणालीगत चलनिधि को व्यवस्थित करने के लिए 14-दिवसीय वीआरआरआर को लागू करते हुए, 3-7 दिनों की परिपक्वता के छह परिष्करण परिचालन और 28-दिन की परिपक्वता की एक लंबी अवधि के लिए वीआरआरआर आयोजित किए गए थे। जनवरी 2022 के पहले अर्धांश में अधिशेष चलनिधि के पुनर्संतुलन को जारी रखते हुए, रिजर्व बैंक ने ₹5.0 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक 14-दिवसीय वीआरआरआर और 3-7 दिनों की परिपक्वता के पांच परिष्करण परिचालन आयोजित किए। परिणामस्वरूप, जनवरी 2022 (13 जनवरी तक) के माध्यम से दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दैनिक चलनिधि अवशोषण औसतन ₹8 लाख करोड़ था, जो पहले अर्धांश में ₹9.4 लाख करोड़ से कम था। साथ ही, नियत दर प्रतिवर्ती रिपो के माध्यम से अवशोषित चलनिधि भी नवंबर-मध्य से दिसंबर 2021-मध्य के दौरान ₹2.2 लाख करोड़ से कम होकर ₹1.5 लाख करोड़ हो गई (चार्ट 34)।

चार्ट 34: अधिशेष चलनिधि



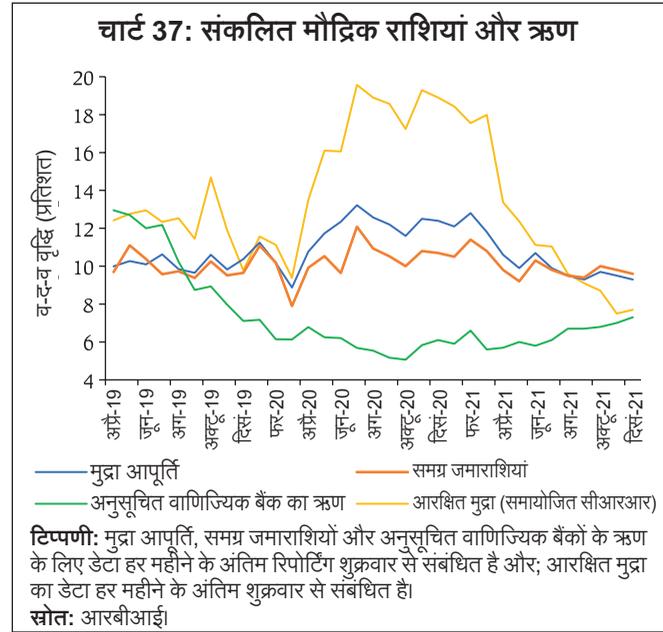
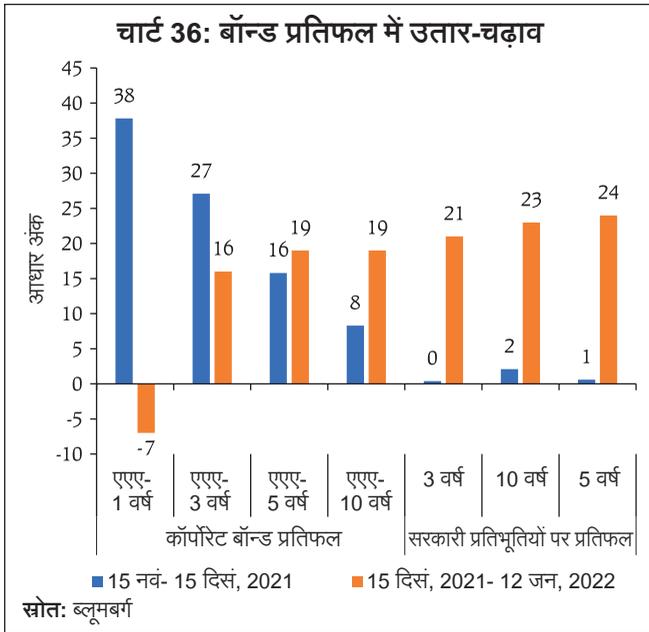


प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर, रिपो दर के आस-पास आ गई (चार्ट 35ए)। वीआरआरआर नीलामियों में उच्च निर्दिष्ट सीमा से संकेत लेते हुए मुद्रा बाजार की दरों में वृद्धि हुई। 3-4 दिनों की परिपक्वता और अग्रिम कर भुगतान की वीआरआरआर नीलामियों की आवृत्ति में वृद्धि दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश में मुद्रा बाजार के अंतिम क्षणों में भारत हुई। एक दिवसीय खंड में जबकि भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), प्रतिवर्ती रिपो दर के आस-पास बनी रही, वहीं जनवरी 2022 में कमी के पूर्वाग्रह के साथ संपार्श्विक खंड में बाजार रिपो और त्रिपक्षीय रिपो दिसंबर के मध्य से अधिक थे। मीयादी खंड में, 3 महीने की राजकोषीय बिल और जमा प्रमाण पत्र (सीडी) दरें प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर के संयोजन के साथ विकसित हुईं; दिसंबर 2021 के दूसरे अर्धांश से 12 जनवरी, 2022 तक, उनके औसत स्प्रेड (प्रतिवर्ती रिपो दर की तुलना में) के साथ क्रमशः 24 और 31 आधार अंकों पर रही। दूसरी ओर, 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी-एनबीएफसी) पर दरें तीव्र प्राथमिक बाजार गतिविधि को देखते हुए उच्च बनीं रहीं (चार्ट 35बी)।

बॉन्ड प्रतिफल उच्चतर बना रहा, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (पुरानी) प्रतिफल लगभग दो साल के उच्च स्तर के आस-पास बनी रही और 14 जनवरी, 2022 को 6.58 प्रतिशत पर बंद हुई है। वैश्विक संकेत, जैसे, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा (जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा अप्रत्याशित वृद्धि) समायोजनकारी रुख को समाप्त करने का संकेत, अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल में वृद्धि और कच्चे तेल की उच्च कीमतों ने रुख को प्रभावित किया और प्रतिफल के स्तर में वृद्धि की। घरेलू प्राथमिक खंड में, 24 दिसंबर, 2021, 7 और 14 जनवरी, 2022 को आयोजित साप्ताहिक नीलामी में प्राथमिक डीलरों (पीडी) पर न्यागमन के साथ उच्च प्रतिफल कट ऑफ हुआ। रिजर्व बैंक ने अस्थिर दर वाले बॉन्ड 2028 (जीओआई एफआरबी 2028) और 6.10 जीएस 2031 के लिए किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया और 31 दिसंबर, 2021 को साप्ताहिक नीलामी में 6.95 जीएस 2061 के लिए सभी बोलियों को स्वीकार किया। मंदी की प्रवृत्ति 31 दिसंबर, 2021 को आयोजित नीलामी के लिए उच्च हामीदारी शुल्क और जनवरी 2022 के पहले दो सप्ताहों में भी परिलक्षित हुई। सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में वृद्धि के संकेतों के आधार पर कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में भी वृद्धि हुई (चार्ट 36)।

<sup>9</sup> प्रभावी प्रतिवर्ती रिपो दर, नियत दर प्रतिवर्ती रिपो दर का भारत औसत और परिष्करण परिचालन सहित सभी परिपक्वताओं के वीआरआरआर हैं, जिसमें भार, संबंधित प्रतिवर्ती रिपो की अवधि के तहत अवशोषित राशि है।

समग्र रूप से, मौद्रिक और ऋण स्थितियां रिजर्व बैंक के विकासोन्मुख समुत्थान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप



विकसित हुई हैं। नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) 31 दिसंबर, 2021 (एक साल पहले 19.1 प्रतिशत) की स्थिति में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई - प्रचलन में मुद्रा जो कि आरएम का सबसे बड़ा घटक है - उसमें 7.8 प्रतिशत (एक साल पहले 22.1 प्रतिशत) का विस्तार हुआ। दूसरी ओर, बैंकों द्वारा सुदृढ़ जमाराशि संग्रहण (10.3 प्रतिशत) के बल पर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति में 9.9 प्रतिशत (एक साल पहले 12.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि, जो अप्रैल 2020 के बाद पहली बार नवंबर 2021 में 7 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई, 31 दिसंबर, 2021 तक 9.2 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले 6.2 प्रतिशत) (चार्ट 37)।

मौद्रिक नीति के रुख पर अधिशेष चलनिधि और आगे के मार्गदर्शन से मौद्रिक संचारण की सुविधा जारी है। मार्च 2020 के बाद से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की एक वर्ष की औसत सीमांत लागत में संचयी रूप से 100 आधार अंकों की कमी आयी है। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक औसत सावधि जमा दर में 154 आधार अंकों की गिरावट आयी है। निधि की कुल लागत में कमी ने बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में

संचारण को सक्षम किया है। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर के लिए रिपो दर में पूर्ण रूप से कटौती की गई है (सारणी 4)।

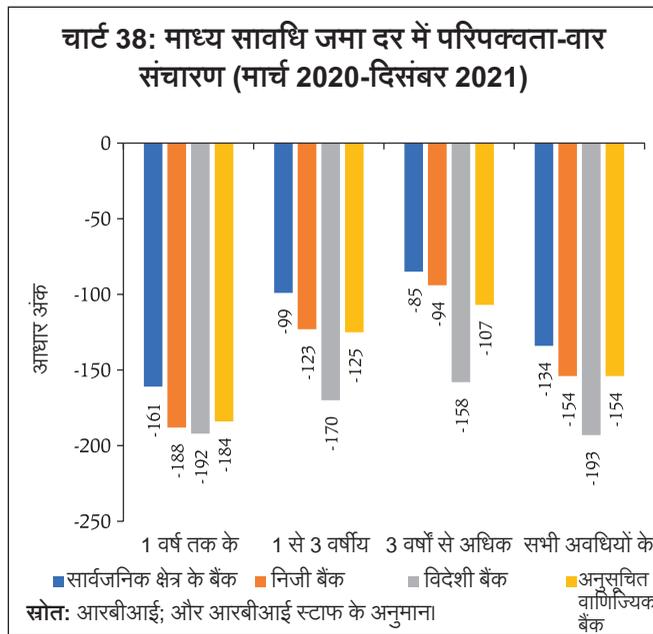
साथ ही, मार्च 2020 से शुरू होने वाली सभी अवधियों में जमाराशि की दरों में भी नरमी आयी है। एक वर्ष की परिपक्वता

#### सारणी 4: रिपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचारण

(आधार अंक में उतार-चढ़ाव)

अवधि	रिपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		टीडीआर माध्य (नई जमाराशियां)	डब्ल्यूएलआर माध्य (बकाया जमाराशियां)	1 वर्षीय एमसीएलआर माध्य	डब्ल्यूएलआर (बकाया रुपया ऋण)	डब्ल्यूएलआर (नये रुपया ऋण)
फर 2019 - सितं 2019	-110	-9	-7	-30	0	-43
अक्टू 2019 - दिसं 2021*	-140	-185	-180	-132	-133	-154
मार्च 2020 - दिसं 2021*	-115	-154	-141	-100	-114	-124
फर 2019 - दिसं 2021*	-250	-213	-187	-155	-133	-197

**टिप्पणी:** डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएलआर पर नवीनतम डेटा नवंबर 2021 से संबंधित है।  
 डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएलआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;  
 एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; टीडीआर: सावधि जमा दरा  
 स्रोत: आरबीआई

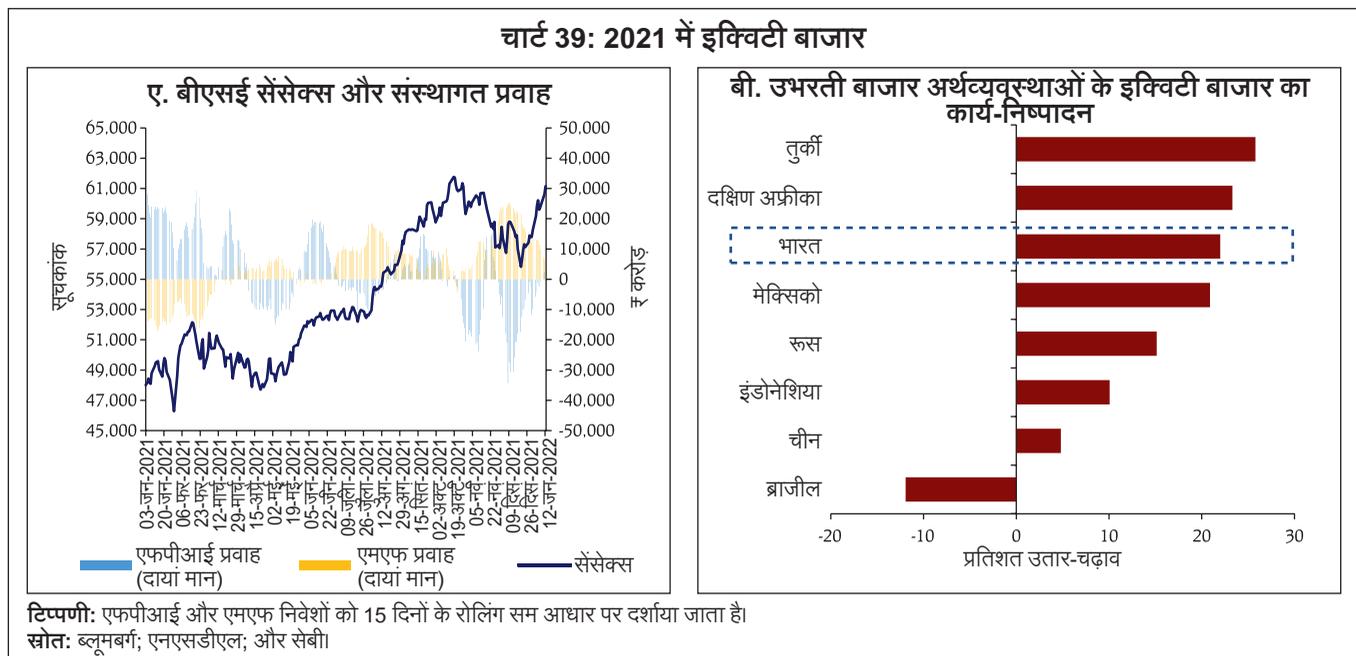


तक की लघु अवधि की जमाराशियों में 184 आधार अंकों की बड़ी गिरावट और 3 वर्षों से अधिक की परिपक्वता की लंबी अवधि की जमाराशियों पर जमा दरों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रभाव अंतरण देखा जा सकता है। घरेलू बैंकों में, निजी बैंकों ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में मीयादी जमा दरों के लिए उच्च प्रभाव अंतरण प्रदर्शित करना जारी रखा है (चार्ट 38)। हाल के

महीनों में, कुछ प्रमुख बैंकों ने जमाराशियों पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे ऋण मांग में तेजी आने की उम्मीद है।

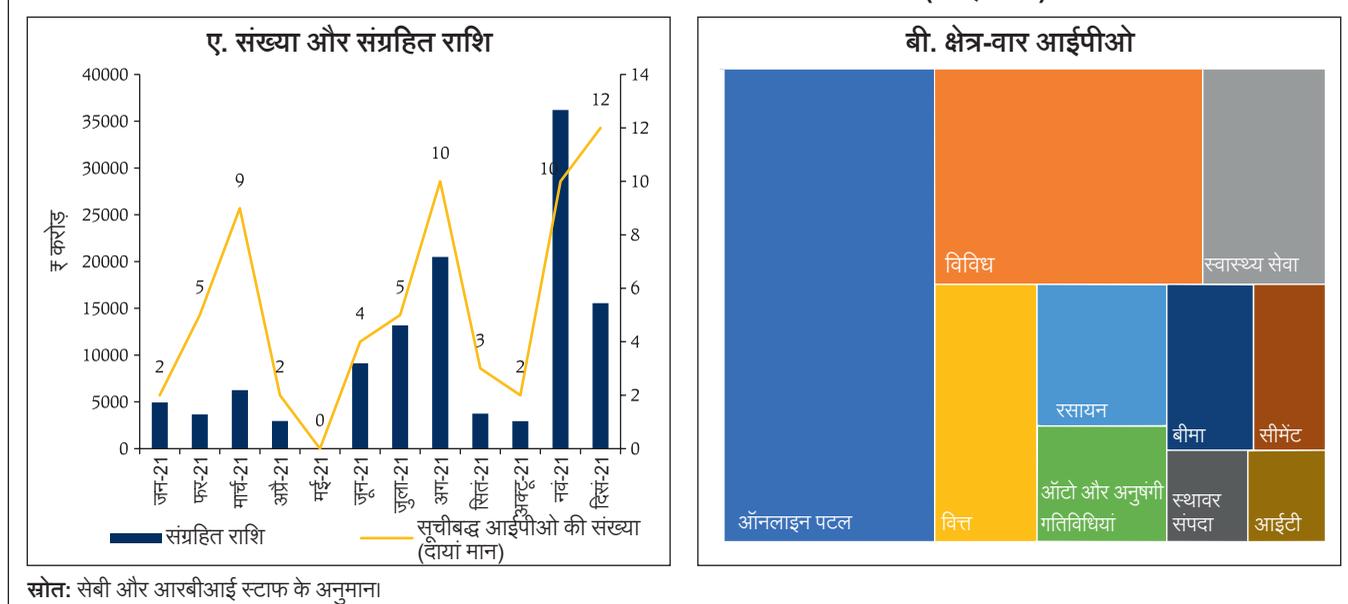
भारत सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को अल्प बचत उपकरणों (एसएसआई) पर ब्याज दरों की समीक्षा की और उन्हें लगातार सातवीं तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा। 2021-22 की चतुर्थ तिमाही के लिए एसएसआई पर वर्तमान ब्याज दरें फॉर्मूला-आधारित दरों की तुलना में 42-168 आधार अंक अधिक हैं<sup>10</sup>

शुरुआत में नीतिगत दर और रुख में यथास्थिति की रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले इक्विटी बाजार दिसंबर 2021 में अस्थिर हो गए, लेकिन बाद में ओमीक्रॉन संस्करण के प्रसार पर चिंताओं के कारण इसे उलटा लाभ हुआ (चार्ट 39ए)। ओमीक्रॉन वैरियंट के प्रसार की गंभीरता पर चिंताओं के साथ, बाजार ने सकारात्मक वैश्विक संकेतों से सीखते हुए अपने नुकसान की भरपाई की। कैलेंडर वर्ष के आधार पर, भारतीय इक्विटी (बीएसई सेंसेक्स) ने 22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, जो अधिकांश उभरते बाजार के प्रतिभागियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था (चार्ट 39बी)। बीएसई सेंसेक्स 2022 में 5.1 प्रतिशत बढ़कर 14 जनवरी, 2022 को 61,223 पर बंद हुआ।



<sup>10</sup> अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा प्रभावी और निर्धारित की जाती हैं। ये प्रभावी ब्याज दरें एक अंतराल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल से जुड़ी होती हैं और तुलनीय परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के ऊपर 0-100 आधार अंकों से लेकर तिमाही आधार पर तय की जाती हैं।

चार्ट 40: 2021 में मेनबोर्ड प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)



दिसंबर 2021 के दौरान, पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड) ने ₹21,923 करोड़ की निवल खरीदारी दर्ज की, जबकि एफपीआई निवल विक्रेता बन गए और घरेलू इक्विटी बाजार में ₹13,150 करोड़ दिये।

दिसंबर में 12 कंपनियों के प्रमुख आईपीओ की सूचीबद्धता के साथ - 2021 में किसी भी महीने के लिए सबसे अधिक (चार्ट 40ए), आईपीओ बाजार में उत्साह बना रहा। इन कंपनियों द्वारा संसाधन जुटाने की राशि ₹15,553 करोड़ थी। वर्ष 2021 आईपीओ बाजार में उछाल का वर्ष साबित हुआ, जिसमें 64 कंपनियों की प्रमुख सूचीबद्धता ने 1.2 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जबकि 14 कंपनियों की प्रमुख सूचीबद्धता ने 2020 में 26,312 करोड़ रुपये जुटाए थे। क्षेत्रवार देखें तो, 2021 में संसाधनों का बड़ा हिस्सा खाद्य वितरण, बीमा, ऑटो और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र (चार्ट 40बी) में काम करने वाली नए युग के मंच आधारित कंपनियों द्वारा जुटाया गया था।

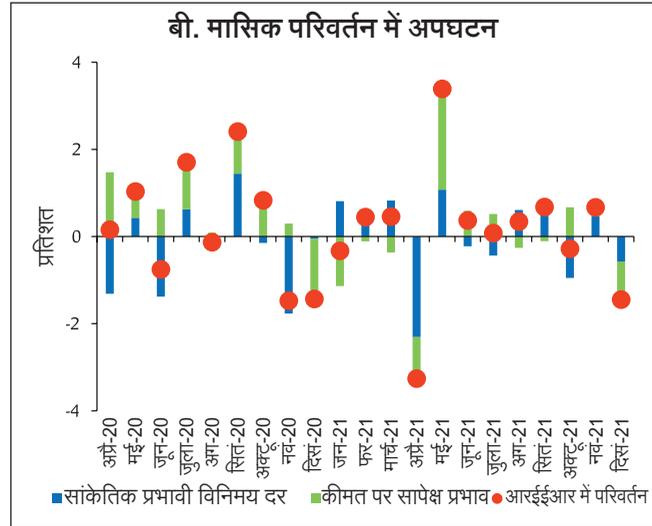
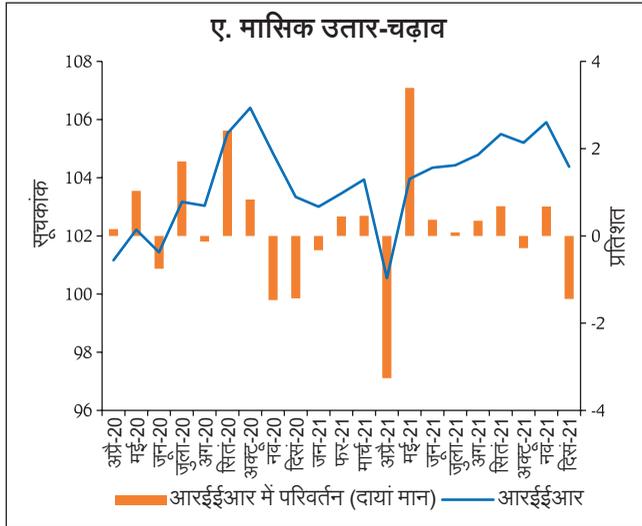
भारत के चालू खाते की शेष राशि में 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी का 0.9% और एक वर्ष पहले जीडीपी का 2.4% के अधिशेष की तुलना में 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 1.3% घाटा दर्ज किया गया। बुनियादी विषयों में उतार-चढ़ाव के कारण, भारतीय रुपये (आईएनआर) में दिसंबर में अमेरिकी डॉलर

के मुकाबले 0.6% (माह-दर-माह) की गिरावट आई। यह 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में आईएनआर के उतार-चढ़ाव में भी प्रतिबिंबित हुआ, जो एक महीने पहले अपने स्तर (चार्ट 41) से 1.4 प्रतिशत कम हो गया था।

सितंबर 2021 के अंत तक भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में मार्च 2021 के अंत में सुधार हुआ, जिसमें भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि ने भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। 2021-22 में विदेशी मुद्रा भंडार में एक मजबूत वृद्धि ने अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) के कवरेज को मार्च 2021 के अंत में 226.9 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 के अंत में 248.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है (सारणी 5)।

कोविड मामलों में अचानक वृद्धि और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से नीतिगत सख्ती के पूर्वानुमानों के कारण विदेशी निवेशकों के बीच मंदी की भावनाओं को बढ़ावा मिला। दिसंबर 2021 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने घरेलू पूंजी बाजार के इक्विटी और ऋण दोनों क्षेत्रों में अपने जोखिम को कम कर दिया (चार्ट 42)। इससे आगे बढ़ते हुए, 2022 में आईपीओ के लिए एक मजबूत पाइपलाइन और वैश्विक

**चार्ट 41: 40 मुद्रा-समूह की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक संचलन (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)**



**टिप्पणी:** दिसंबर 2021 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।  
**स्रोत:** आरबीआई

बॉन्ड सूचकांकों में सरकारी बॉन्ड के संभावित समावेश से एफपीआई अंतर्वाह को बढ़ाया जा सकता है।

भारत को विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का निवल संवितरण (अंतर-कंपनी उधार सहित) एक वर्ष पहले 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। नवंबर में उठाए गए ईसीबी के एक बड़े हिस्से का उपयोग नई परियोजनाओं

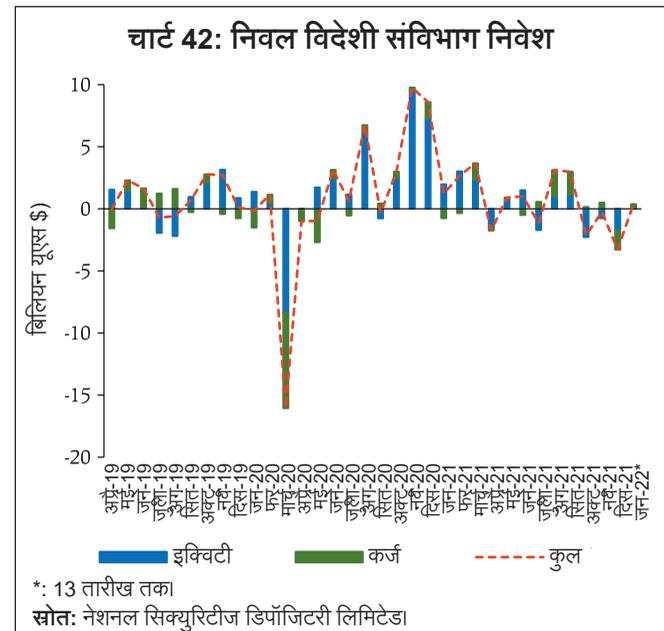
और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आगे उधार देने/पुनः-उधार देने के लिए किया गया था।

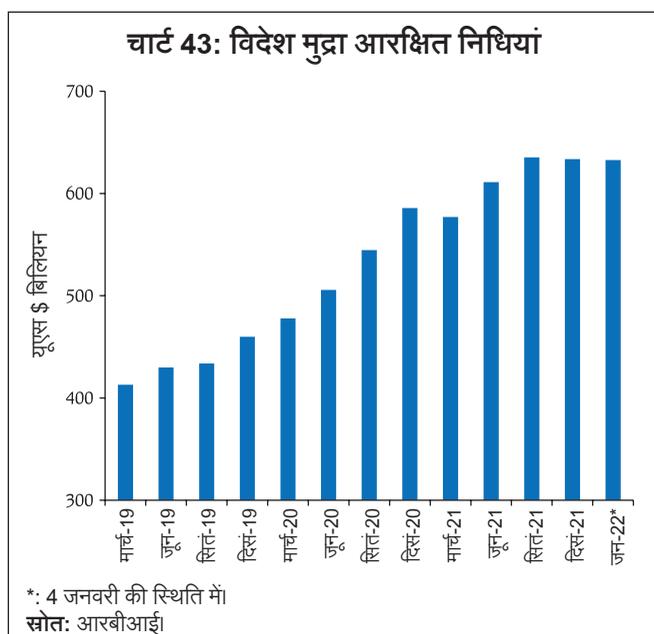
07 जनवरी, 2022 (चार्ट 43) को विदेशी मुद्रा भंडार 632.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 के लिए अनुमानित आयात के 13 महीनों के बराबर कवर प्रदान करता है।

**सारणी 5: प्रमुख बाहरी भेद्यता संकेतक**

संकेतक	मार्च, 2021 की समाप्ति पर	सितंबर, 2021 की समाप्ति पर
1. बाह्य ऋण (बिलियन यूएस \$)	569.6	593.1
2. जीडीपी अनुपात के लिए बाह्य ऋण (%)	21.1	20.1
3. कुल ऋण अनुपात के लिए अल्पकालिक ऋण (आरएम)	44.6	43.2
4. कुल ऋण अनुपात के लिए आरक्षित निधियां (%)	101.3	107.1
5. अल्पकालिक ऋण (आरएम) अनुपात के लिए आरक्षित निधियां (%)	226.9	248.2
6. आयात का आरक्षित निधियों का कवर (महीनों में)	17.4	14.6
7. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)# (बिलियन यूएस \$)	-351.1	-331.8
8. निवल आईआईपी/ जीडीपी अनुपात (%)#	-13.1	-11.6

आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता।  
आईआईपी: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति।  
#: ऋणात्मक संकेत भारत पर अनिवासियों के निवल दावों को इंगित करते हैं।  
**स्रोत:** आरबीआई।





### भुगतान प्रणाली

वर्ष 2021 में स्थिर वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित करते हुए थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान लेनदेन की स्थिति दिसंबर में उत्साहजनक रही (सारणी 6)। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के तहत संसाधित लेनदेन मूल्य लगातार तीसरे महीने बढ़े, जबकि वॉल्यूम बढ़कर 1.92 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक था। खुदरा मोर्चे पर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), नेशनल ऑटोमेटेड

किलयरिंग हाउस (एनएसीएच) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भुगतान ने एक महीने पहले अपने स्तर से दिसंबर में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने एक और ऊँचाई हासिल की, जिसमें 456 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लेनदेन हुआ, जिसका रिकॉर्ड मूल्य ₹8.26 लाख करोड़ था। गतिशीलता में उत्साहित गति को दर्शाते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल उगाही (एनईटीसी) के माध्यम से लेनदेन के मात्रा और मूल्य अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कुल मिलाकर, प्रमुख भुगतान चैनलों में दैनिक औसत लेनदेन का मूल्य पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है।

भारत के डिजिटल भुगतान परितंत्र ने 2021 में अच्छा विस्तार दर्ज किया। आरटीजीएस की कुल मात्रा में 37 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि मूल्यों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूपीआई चैनल के माध्यम से लेनदेन, मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टिकोण से दोगुने से अधिक हो गए हैं। अन्य प्रमुख खुदरा भुगतान तरीके, जैसे- एनईएफटी, आईएमपीएस, एनईटीसी और बीबीपीएस में भी वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि देखी गई।

3 जनवरी 2022 को, रिजर्व बैंक ने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों, जैसे चैनलों के माध्यम से ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा जारी की। इस तरह के भुगतान को, प्रति लेनदेन ₹200 के साथ सभी लेनदेन के लिए ₹2000 की कुल सीमा तक सीमित कर दिया गया है। इस कदम से सीमित इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले दूरदराज

### सारणी 6: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेन-देन की मात्रा में वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)				(लेन-देन के मूल्य में वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)			
	नव-2020	नव-2021	दिसं-2020	दिसं-2021	नव-2020	नव-2021	दिसं-2020	दिसं-2021
आरटीजीएस	2.9	24.9	20.2	17.9	-8.0	37.5	3.3	21.7
एनईएफटी	24.6	24.1	31.6	22.3	27.9	4.3	31.7	6.5
यूपीआई	81.3	89.4	70.8	104.4	106.6	96.5	105.5	98.7
आईएमपीएस	48.7	21.5	38.7	24.5	36.3	31.9	38.6	35.6
एनएसीएच	2.5	15.7	28.0	-2.7	5.7	7.1	32.2	5.1
एनईटीसी	257.6	71.5	115.2	74.9	171.6	51.1	83.3	59.7
बीबीपीएस	78.7	148.6	86.2	137.0	78.1	175.3	97.9	165.2

स्रोत: आरबीआई

के क्षेत्रों में डिजिटल उपयोग बढ़ने और इससे डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है<sup>11</sup>

कार्ड-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को बेहतर बनाने और ग्राहक की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने मर्चेट प्लेटफॉर्म पर ग्राहक-कार्ड की सूचनाएँ संगृहीत करने पर रोक लगा दी है और 31 दिसंबर 2021 से कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उद्योग के पणधारियों के अभ्यावेदन के बाद, इन मानदंडों के अनुपालन की समय-सीमा 6 महीने - यानी 30 जून 2022 तक - बढ़ा दी गई है ताकि टोकन-आधारित कार्ड लेनदेन की ओर परिवर्तन आसान हो सके।<sup>12</sup> डिजिटल भुगतान तरीकों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1,300 करोड़ की एक योजना शुरू की है।<sup>13</sup>

जनवरी 2022 के शुरुआती आंकड़ों (12 जनवरी तक) से डिजिटल भुगतान में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, हालांकि संक्रमण में हालिया उछाल आगे चलकर चिंता का विषय बन सकता है। फिर भी, विभिन्न चेकआउट विकल्पों की उपलब्धता और बढ़ती डिजिटल जागरूकता को देखते हुए भुगतान उद्योग से लचीलापन अपेक्षित है। बाज़ार-अनुमानों के अनुसार डिजिटल भुगतान का मूल्य, वित्त वर्ष 2021 के यूएस \$ 300 बिलियन से वित्त वर्ष 2026 तक यूएस \$ 01 ट्रिलियन तक, तीन गुना बढ़ सकता है।<sup>14</sup>

## निष्कर्ष

उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास आशाजनक के होने और उच्च आवृत्ति संकेतकों में वृद्धि के कारण भारत में समग्र आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है। टीकाकरण के मोर्चे पर भारत ने तेज प्रगति की है। ओमीक्रॉन वेरियंट पर, यूके और दक्षिण अफ्रीका के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह के 66 से 80 प्रतिशत संक्रमण हल्के होते हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कम होती है।<sup>15</sup> इससे निकट अवधि की संभावनाएँ आशाजनक हैं और वित्तीय बाजार सकारात्मक हैं।

साथ ही, बैंक ऋण में धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि से मौद्रिक और ऋण की स्थिति सुधर रही है। भारत के डिजिटल भुगतान परितंत्र में तीव्र विस्तार हो रहा है। इसके विपरीत, वैश्विक परिदृश्य काफी अनिश्चित हैं। उत्पादन, आपूर्ति शृंखला और परिवहन में व्यवधानों के कारण सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। नतीजतन, देशों के मौद्रिक नीति के रुख में अंतराल व्यापक हो गया है। ऐसे संकेत हैं कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और पोत-परिवहन लागत धीरे-धीरे कम हो रही हैं, हालांकि मुद्रास्फीति कम होने में अधिक समय लग सकता है। यह वैश्विक सुधार को तेज और व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय है।

<sup>11</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12215&Mode=0>

<sup>12</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12211&Mode=0>

<sup>13</sup> [https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/eGazette\\_Notification\\_Incentive%20Scheme\\_17thDec2021.pdf](https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/eGazette_Notification_Incentive%20Scheme_17thDec2021.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/digital-payments-in-india-will-reach-1-trillion-by-fy26-estimates-clsa-7823371.html>

<sup>15</sup> एफटी, 10 जनवरी, 2022